

‘कांग्रेस ने सांप्रदायिक एजेंडा के तहत वंदे मातरम् के संक्षिप्त संस्करण को राष्ट्र गीत बनाया’

संसद में वंदे मातरम् पर बहस की शुरुआत करते हुए प्र.मंत्री मोदी ने कांग्रेस पर वंदे मातरम् का अपमान करने का आरोप लगाया

- जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 8 दिसम्बर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में ‘वंदे मातरम्’ की 150 वीं वर्षगांठ पर हुई चर्चा में कांग्रेस पर तीखा हमला किया और भारत के राष्ट्रीय गीत को विपक्षी पार्टी की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 50 साल पहले लगाए गए आपातकाल से जोड़ने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि उनके एक और पूर्ववर्ती, जवाहरलाल नेहरू, ने ‘वंदे मातरम्’ का विरोध करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना का अनुसरण किया था, क्योंकि यह “मुसलमानों को नाराज कर सकता था।” उन्होंने कहा, “जब ‘वंदे मातरम्’ को लिखे 100 वर्ष हुये थे, तब देश आपातकाल में फंसा हुआ था... जब यह अपने 100 वें वर्ष में था, तब संविधान का गला घोट दिया गया था।” प्रधानमंत्री ने कहा, “अब, 150 साल बाद, यह ‘वंदे मातरम्’ की महिमा

- प्र.मंत्री ने कहा, बकिम चंद्र ने जो वंदे मातरम् लिखा था उसके शुरुआती दो अंतरे राष्ट्र गीत में रखे गए, शेष 6 अंतरे हटा दिए गए, क्योंकि उसमें हिंदू देवियों, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का संदर्भ दिया गया था, यह कांग्रेस का सांप्रदायिक एजेंडा था।
- प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 1875 में वंदे मातरम् की रचना हुई थी। अब इसकी 150वीं जयंती है. यह अच्छा अवसर है, इसकी महिमा बहाल करने का।

को बहाल करने का एक अच्छा अवसर है... जिसने हमें 1947 में स्वतंत्रता दिलाई थी।” उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1875 में लिखे गए इस गीत की सराहना की, और कहा कि यह जल्द ही स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक नारा बन गया था। “हमने हाल ही में अपने संविधान की 75 वीं वर्षगांठ मनाई। देश ने सरदार वल्लभभाई पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई। हम गुरु तेग बहादुर जी का 350वें शहीदी दिवस भी मना रहे हैं। अब हम ‘वंदे मातरम्’ के

के तहत इसका अनादर किया था और इसे इसके संक्षिप्त रूप में देश का राष्ट्रीय गीत बना दिया था। इस विवाद के केन्द्र में इसके छः अन्तरे हैं, जिनमें चट्टोपाध्याय ने हिन्दू देवी दुर्गा, कमला (या लक्ष्मी) और सरस्वती का संदर्भ दिया था, और इन्हें भारत की संरक्षक के रूप में प्रस्तुत किया था। 1937 में, कांग्रेस, जिसके अध्यक्ष उस समय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ने राष्ट्रीय समारोहों में इसके केवल पहले दो अन्तरे (स्टैन्डा) गाने का निर्णय लिया था। इसका तर्क यह था कि हिन्दू देवियों के सीधे संदर्भ मुस्लिम समुदाय के कुछ सदस्यों द्वारा अच्छी तरह से नहीं लिए गए थे; इन्हें “बहिष्कार योग्य” माना गया था। प्रस्ताव में लिखा था: “सभी बातों पर विचार करते हुए, समिति यह सिफारिश करती है कि जब भी ‘वंदे मातरम्’ राष्ट्रीय समारोहों में गाया जाए, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वन रक्षक भर्ती का इनामी फरार आरोपी गुजरात से गिरफ्तार

जयपुर, 8 दिसम्बर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने कार्रवाई करते हुए वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर लीक मामले में पचास हजार रुपये के इनामी फरार आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी वन रक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक करने में अहम कड़ी है। गैंग के लोगों ने किन-किन लोगों को पेपर बेचा और कहाँ से लीक पेपर मिला, एसओजी की टीम यह पृष्ठताछ करने में जुटी है। एसओजी एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि ‘फरार आरोपी जबराम को

- एसओजी को आशा है कि इससे पूछताछ में यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि लोक पेपर कहाँ से हासिल किया तथा किस-किस को बेचा।

गुजरात से पकड़कर बांसवाड़ा लाया गया है और अब उससे पूछताछ की जाएगी।

एसओजी की पूछताछ के बाद सामने आएगा कि परीक्षा का पेपर लीक गैंग ने कहाँ से हासिल किया था और किन-किन लोगों को परीक्षा का पेपर बेचा गया था। आरोपी जबराराम सरकारी शिक्षक है और वनरक्षक भर्ती (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इंडिगो ही नहीं सभी भारतीय एयरलाइन्स बारूद के ढेर पर काम कर रही हैं

एक छोटी सी गलती, चिंगारी का काम करती है, पूरे सैक्टर को ढेर करने में

- एयरलाइन्स को टाइट बजट में काम करना होता है. हवाई जहाज़ के पेट्रोल पर भारी टैक्स है. हवाईअड्डों की क्षमता बहुत सीमित ही नहीं कम है. सैक्टर का संचालन करने वाले रेग्युलेटरी ढांचे का काम करने का तरीका अनिश्चित सा, लगभग मनमर्जी से चलने वाला लगता है।
- इंडिगो एयरलाइन्स के अनुभव ने यह जता ही दिया कि जब केवल एक्सपेंशन पर भारी जोर हो तो सिस्टम इतना नाजुक हो जाता है कि किसी भी दिक्कत से जूझकर, उसका सामना करके आगे बढ़ने की क्षमता उसमें नहीं रह जाती और तूफान तो दूर की बात है, हवा का झोंका ही ताश् के पत्ते के किले को ढहा देता है।
- सैक्टर को सुव्यवस्थित चलाए रखने के लिए गठित “रैग्युलेटरी सिस्टम” (नियंत्रक व्यवस्था) का रूख प्रतिक्रियात्मक है न कि दुर्घटना से पहले, दुर्घटना रोकने का इंतज़ाम करने वाला।
- इस सैक्टर का आधारभूत ढांचा- रनवे, पार्किंग स्थल, गेट्स, एरोब्रिज तथा ग्राउंड हैंडलिंग साधन इतने सीमित हैं कि किसी एक में कुछ गड़बड़ी हुई तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है।

मुर्शिदाबाद के बाद, ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा हुई

यू.पी. के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तीखी प्रतिक्रिया की कि मस्जिद बनाने पर कोई आपत्ति नहीं है, पर, अगर यह मस्जिद बाबर के नाम पर बनाई जाती है तो सख्त आपत्ति होगी।

- श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 8 दिसम्बर। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की एक प्रतिकृति बनाने की योजनाओं ने भाजपा के बीच भारी हलचल मचा दी है, यह विवाद अब और बढ़ता हुआ दिख रहा है, जब ‘तहरीक मुस्लिम शब्बन’ नामक एक समूह ने हैदराबाद के ग्रेटर इलाके में बाबरी मस्जिद स्मारक बनाने की योजना की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में, निर्लंबित तृणमूल विधायक हुमायूँ कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले में पहले मुगल सम्राट बाबर के नाम पर मस्जिद का शिलान्यास करने के अपने निर्णय से विवाद खड़ा कर दिया। इस विवाद पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई, जिन्होंने कहा कि भाजपा न केवल इस निर्माण का विरोध करेगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित

- हैदराबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का एलान करने वाले तहरीक मुस्लिम शब्बन के अध्यक्ष मुश्ताक मलिक ने इस पर कहा, “किसी को भी बाबर के नाम पर आशंकित नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं कि अयोध्या मस्जिद के निर्माण में बाबर का कुछ पैसा लगा था। यह संभव है कि पुरानी बाबरी मस्जिद किसी स्थानीय व्यक्ति बाबर के नाम पर बनी हो। भाजपा व आरएसएस इस बात को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। बाबर का शासनकाल तो बहुत छोटा था।”

करेगी कि इसे जल्दी से तोड़ा जाए। “मस्जिद के निर्माण में कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कोई इसे बाबर के नाम पर बनाता है, तो इसे मजबूत विरोध का सामना करना पड़ेगा।” पश्चिम बंगाल में अगले साल के शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, और आस्था के मुद्दे पर भाजपा को यह मसला प.बंगाल में साम्प्रदायिक

सुनील शर्मा राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त



सुनील शर्मा

जयपुर, 8 दिसम्बर (कासं)। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने सोमवार को आदेश जारी कर सेवानिवृत्त आई.ए.एस. सुनील शर्मा को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। यह नियुक्ति पदभार ग्रहण करने से 3 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, के लिए की गई है। ज्ञात रहे कि सुनील शर्मा इस साल अप्रैल में ही सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। शर्मा, वर्ष (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘इंडिगो संकट के झटके बिहार की सरकार में भी महसूस हुए

नीतीश की पार्टी जद (यू) ने पुरजोर ढंग से मांग उठाई की इंडिगो की “दिन दहाड़े डकैती” के खिलाफ सख्त और तुरंत कार्यवाही करे सरकार

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 8 दिसंबर। इंडिगो एयरलाइंस में चल रहे संकट ने सत्ताधारी एनडीए में अप्रत्याशित राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है, जिसमें गठबंधन सहयोगी हवाई उड़ानों की किराया वृद्धि और देशभर में व्याप्त संकट के चलते सार्वजनिक रूप से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इस स्थिति ने मोदी सरकार को असामान्य रूप से रक्षात्मक स्थिति में ला दिया है, क्योंकि प्रमुख सहयोगी तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की मांग कर रहे हैं और निजी एयरलाइनों पर “दिनदहाड़े लूट” करने का आरोप लगा रहे हैं।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी रहे एक वरिष्ठ जदयू नेता ने बुधवार को इंडिगो के दफ्तर के बाहर धरना देने की धमकी दी, एयरलाइन पर अफरातफरी के बीच यात्रियों का शोषण करने का आरोप लगाया। उनका यह

- जद (यू) नेता व एनडीए के जाने माने चेहरे के.सी. त्यागी ने एक व्यक्तिगत जानकारी देकर और हड़कंप मचा दिया कि “उन्हें अपनी बेटी के दिल्ली-मुंबई टिकट के लिए इकतालीस हजार का नाजायज भुगतान करना पड़ा। त्यागी ने एयरलाइन्स से यह राशि लौटाने की मांग की तथा केन्द्रीय सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की “डिमांड” उठाई।
- त्यागी के अनुसार, यह मार्केट प्राइसिंग” नहीं है, बल्कि संकट के नाम पर शोषण है।
- पहली बार सरकार को विरोध का सामना विपक्ष की ओर से ही नहीं, अपने सहयोगी पार्टी की तरफ से करना पड़ रहा है।

आक्रोश एनडीए के भीतर गहरी निराशा को दर्शाता है, जो, साक्षेदारों के अनुसार, नागरिक विमानन क्षेत्र में शासकीय और नियामक विफलता का परिणाम है। इस दबाव को और बढ़ाते हुए, वरिष्ठ जदयू नेता और एनडीए का प्रमुख

चेहरा के.सी. त्यागी ने सरकार को एक व्यक्तिगत खुलासा करके चौंका दिया कि उन्हें अपनी बेटी के दिल्ली-मुंबई टिकट के लिए 41,000 रुपये की भारी राशि का भुगतान करना पड़ा। इसे “पूर्णतया लूट” बताते हुए, त्यागी ने

एयरलाइन से तत्काल रिफंड की मांग की और केन्द्र से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। “यह बाजार मूल्य निर्धारण नहीं है। यह संकट के नाम पर शोषण है”, त्यागी ने पार्टी के सहयोगियों से कथित तौर पर कहा, यह संकेत देते हुए कि नाराजगी न तो प्रतीकात्मक है और न ही राजनीतिक रूप से मंचित। अंदरूनी सरकार सूत्र इस विवाद पर चुपची साधे हुए हैं, जबकि इस घटना ने केन्द्र के संकट प्रबंधकों के लिए एक अजीब और असहज स्थिति उत्पन्न कर दी है, जो पहले ही विमानन क्षेत्र में एक प्रमुख निजी एयरलाइन पर अत्यधिक निर्भरता के कारण आलोचना का सामना कर रहे हैं। मोदी सरकार कई मोर्चों पर समस्याओं का सामना कर रही है, यात्रियों के गुस्से और किराए के उतार-चढ़ाव से लेकर नियामक निगरानी, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जापान में भारी भूकंप, सुनामी की चेतावनी

टोक्यो, 08 दिसंबर। जापान में सोमवार को भूकंप के भीषण झटके से कांप उठा। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई है। भूकंप के तुरंत बाद जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने सुनामी की चेतावनी जारी की है। इस कारण जापान के उत्तर-पश्चिमी तट पर तीन मीटर (10 फीट) ऊंची सुनामी आ

- रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई है।

सकती है। मछुआरों और छोटी बोट को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। भूकंप का केंद्र मिसावा शहर से लगभग 73 किलोमीटर उत्तर-पूर्व की ओर स्थित था, जिसकी गहराई लगभग 53 किलोमीटर मापी गई। यह उथले श्रेणी का भूकंप माना गया, जो आमतौर पर अधिक तीव्र झटकों का कारण बनता है। जापान प्रशांत, फिलीपीन सागर, यूरेशियन और उत्तर अमेरिकी प्लेटों के संगम पर स्थित है।

‘सरकार ने वंदे मातरम् पर बहस इसलिए रखी क्योंकि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं’

प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि सरकार हमें अतीत में उलझाए रखना चाहती है और वर्तमान व भविष्य पर बात नहीं करना चाहती

- डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 8 दिसम्बर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा ने आज लोकसभा में वंदे मातरम् पर हुई बहस के दौरान, प्रधानमंत्री और भाजपा पर तीखा लेकिन चुटीला वार किया और प्रधानमंत्री की नेहरू पर बार-बार की जाने वाली आलोचना पर कड़ा हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान जितना समय जेल में बिताया था, वह लगभग उतना ही है, जितना समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के सर्वोच्च पद पर बिताया है। वे वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर हो रही विशेष चर्चा में बोल रही थीं। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को सुझाव दिया कि वे जवाहरलाल नेहरू के लिए की गई सारी आलोचनाओं और अपमानों की एक पूरी सूची बना लें।

उन्होंने कहा, “चाहे वे 999, हों या 9,999-आप एक सूची बना लीजिए, और फिर हम तय कर सकते हैं कि इस पर कब चर्चा करनी है, जैसे हम वंदे मातरम् पर 10 घंटे, बहस कर रहे हैं। जितनी देर आप चाहें, उतनी देर हम बहस करने को तैयार हैं। लेकिन संसद के कीमती समय का इस्तेमाल उस काम के लिए होना चाहिए, जिसके लिए लोगों ने हमें चुना है। एक बार और हमेशा के लिए, इस अध्याय को बंद कर दें।” उनके इतना कहते ही विपक्षी सांसदों की ओर से जोरदार करल-ध्वनि हुई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, नेहरू नौ बार जेल गए और कुल मिलाकर 3,200 से अधिक दिन, यानी लगभग नौ वर्ष, जेल में रहे।

- प्रियंका गांधी ने कहा, भारत के पहले प्रधानमंत्री पं. नेहरू ने कहा था, वंदे मातरम् पर विवाद साम्प्रदायिक ताकतों ने गढ़ा था।
- प्रियंका ने अपने तर्क के पक्ष में नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच लिखी गई चिट्ठियों का उल्लेख किया। गुरुदेव टैगोर ने लिखा था, जिन दो पदों का हमेशा गायन होता रहा है, वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें शेष गीत से अलग करने में कोई समस्या नहीं है और आज़ादी के आंदोलन में सभी इन दो पदों को ही गाते थे।
- टैगोर ने यह भी लिखा था कि इस गीत में बाद के जो पद हैं, उन्हें उस दौर के माहौल को देखते हुए सांप्रदायिक कहा जा सकता है।

प्रियंका गांधी ने आगे कहा, “देश सुन लेगा कि इंदिरा जी ने क्या किया,

राजीव जी ने क्या किया, वंशवादी राजनीति क्या है, नेहरू की क्या गलतियाँ थीं-आइए, इन सब पर बात कर लेते हैं और फिर इसे हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। फिर हम बेरोजगारी और महँगाई पर बात कर पाएँगे।” उनके इस बयान पर भी विपक्षी बेंचों ने जोरदार करल-ध्वनि की।

इससे पहले, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने वंदे मातरम् पर यह बहस अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए आयोजित की है। प्रियंका ने कहा, “यह बहस इसलिए करवाई जा है, ताकि जनता का ध्यान भटक गया जा सके, क्योंकि यह सरकार मौजूदा हालात की सच्चाई छिपाना चाहती है।”

वायनाड की सांसद ने यह भी सवाल उठाया कि संसद में वंदे मातरम् पर बहस की जरूरत ही क्या है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि यह गीत “देश के हर हिस्से में जीवित है और सम्मानित है।” उन्होंने कहा कि सरकार वंदे मातरम् पर चर्चा इसलिए चाहती है, क्योंकि जल्द ही बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। सरकार चाहती है कि हम अतीत में उलझे रहें, क्योंकि वह वर्तमान और भविष्य पर बात करना नहीं चाहती।” प्रियंका गांधी वाड़ा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस प्रकरण को गलत रूप में पेश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नेहरू, जो उनके परदादा और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ने वंदे मातरम् को लेकर हुए उस विवाद को “सांप्रदायिक ताकतों द्वारा खड़ा किया गया विवाद” कहा था। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गोवा अग्निकांड के आरोपी थाइलैंड फरार

गोवा, 08 दिसंबर। गोला क्लब हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। गोवा अग्निकांड के आरोपी थाईलैंड भागने में कामयाब हो गए हैं। अब गोवा पुलिस ने सीबीआई के जरिए इंटरपोल से मदद मांगी है। जिस

- गोवा पुलिस ने यह जानकारी दी। दोनों आरोपी सौरभ और गौरव भाई हैं तथा उस बार के मालिक हैं, जहां हादसा हुआ।

दिन घटना हुई, उसी दिन आरोपियों ने मुंबई से फुकेट (थाईलैंड)की फ्लाइट पकड़ी और भारत से बाहर भाग गए। डीजोपी गोवा आलोक कुमार के अनुसार ये खबर निकलकर सामने आई है। ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन से से जानकारी मिली कि दोनों मालिक आग लगने के तुरंत बाद 7 दिसंबर को सुबह 05.30 (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

जनता की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है। –कहावत

मिनिमम गवर्नेंस, नो गवर्नमेंट

प्रधानमंत्री मोदी ने जब 2०14 में प्रधानमंत्री का पद संभाला था तो यह घोषणा की थी कि वे “मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट” का सिद्धांत लागू करेंगे और इस दिशा में कार्य करेंगे। प्रारंभ के कुछ निमित्तों से ऐसा लगा कि सरकार उसी ओर चल रही है, किंतु जैसे–जैसे समय निकलता गया, यह नारा केवल नारा ही बनकर रह गया। वास्तव में सरकार की कार्यप्रणाली किसी और ही दिशा में चलने लगी। निजीकरण को बहुत अधिक महत्व दिया जाने लगा, जिसमें कोई बुराई भी नहीं थी, किंतु इसके बेलगाम होने का क्या परिणाम हो सकता है, यह हाल ही के दिनों में कई स्थानों पर देखने में आया है।

गत सप्ताह में इंडिगो एयरलाइंस से यात्रा करने वाले यात्रियों को दुर्दशा एवं लाचारी के जो दृश्य, विभिन्न मीडिया माध्यमों पर दिखाए गए, चाहे वे टीवी चैनल हों, सोशल मीडिया हों अथवा प्रिंट मीडिया, बड़े हृदय विदारक थे। कई ऐसे बुजुर्ग थे जो घंटों, बिना दवा के एयरपोर्ट पर बैठे रहे, कई डॉक्टर सर्जरी करने नहीं पहुँच पाए, जिन मरीजों की किसी दूसरे शहर में सर्जरी होनी थी, वह नहीं हो पाई। कुछ मामलों में तो नव दंपति अपने खुद के रिसेप्शन में भी सम्मिलित नहीं हो पाए और उन्हें केवल वीडियो के माध्यम से सम्मिलित होना पड़ा। बिलखते बच्चे और रोती हुई आक्रोशित महिलाओं के दृश्य प्रतिदिन आ रहे हैं। फ्लाइट 2० घंटों के विलंब से जा रही थी। हजारों फ्लाइट्स कैसिल हो गईं। हजारों लोग परीक्षा और इंटरव्यू देने से वंचित रह गए। बहुत से लोगों को विदेशी की कर्मकिर्ता फ्लाइट छूट गई। इंडिगो के कर्मचारियों के पास केवल एक ही रटा रटया उत्तर था कि तकनीकी कारणों से विलंब हो रहा है, फ्लाइट रीशेड्यूल कर रहे हैं अथवा कैसिल हो रही है। भारत में नागरिक की स्थिति कितनी दयनीय हो गई है, यह इसी से पता लगता है कि कोई स्पष्ट उत्तर देने वाला नहीं था कि उनकी फ्लाइट गंतव्य के लिए कब और कितने बजे खाना होगी? जिन लोगों को अत्यावश्यक रूप से कहीं जाना था इसके लिए उन्हें वैकल्पिक फ्लाइट के टिकट, अन्य एयरलाइंस से मनमानी कीमत पर खरीदने पड़े। ऐसा देखा गया कि जिन दो शहरों के बीच में सामान्य टिकट की दर 7– 8000 रुपए थी, वहां के लिए 30000 से 1०0000 रुपए तक लोगों को मजबूरी में देने पड़े।

इंडिगो ने केवल यह कहकर अपने कर्तव्य को इतिश्री कर ली और यात्रियों पर ‘उपकार’ कर दिया कि वह यात्रियों को फ्लाइट रह होने पर पूरा किराया रिफंड करेगी। यह नहीं सोचा कि रिफंड तो 7००0 रुपए का होगा लेकिन नया टिकट 7०००0 रुपए का होगा। यही स्थिति कुंभ मेले के समय भी हुई थी जब 5००0 के स्थान पर लोगों को 50000 रुपए तक देने पड़े थे।

यह सब होते हुए भी सरकार आँखें मूंद कर बैठी रही। उसने न तो एयर लाइन पर कोई जुर्माना लगाया न यात्रियों को कोई मुआवजा देने के लिए इंडिगो को बाध्य किया। यह उल्लेखनीय है कि भारत के विमानन उद्योग में इंडिगो का हिस्सा लगभग 65 प्रतिशत है, अर्थात इसका एकाधिकार है। स्पष्ट है इंडिगो कंपनी निश्चित है कि डी जी सी ए या उड्डयन मंत्रालय उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेगा। यह अति आत्मविश्वास शायद इसलिए कि सितंबर, 2025 से प्रधानमंत्री के अत्यन्त करीबी नीति आयोग के पूर्व सी ई ओ, इंडिगो के निदेशक बन गए हैं। कहा भी गया है, “सैंया भए कोतवाल तो डर काहे का”? एयरलाइंस पर कोई कार्रवाई न करने को जनता के हितों की अनेखी करना ही कहा जाएगा। इंडिगो ने न तो यात्रियों के लिए होटल की व्यवस्था की न खाने की। स्थिति तो यह है कि विगड्ड गई कि एक बुजुर्ग द्वारा जब अपनी लेटी के लिए एयरलाइंस स्टाफ से सैनिटरी नेपकिन की मांग की गई तो वह तक उपलब्ध नहीं कराया गया। लोग 5 घंटे से लेकर 2० घंटे तक अनिश्चिता की हालत में विभिन्न एयरपोर्ट पर बैठे रहे। एयरपोर्ट पर भीड़ की स्थिति किसी शहर के वस अड्डे से भी खराब हो गई थी।

आज प्रत्येक नागरिक यह प्रश्न पृष्ठ रहा है कि क्या सरकार का ‘मैक्सिमम गवर्नेंस’ का यही तात्पर्य है कि यात्रियों को निजी कंपनियों की दया पर छोड़ दिया जाए? उल्लेखनीय है कि इंडिगो का मुनाफा केवल वित्तीय वर्ष 2०24 में ही आठ हजार करोड रुपए से अधिक था। क्या सरकार इस कंपनी को अडेस नहीं दे सकती है कि वह पीडित यात्रियों को कम से कम एक लाख रुपए का मुआवजा दे? नागरिक उड्डयन मंत्रालय जिसके पास विभिन्न एयरलाइन एवं हवाई यात्राओं को नियमित करने की जिम्मेदारी है, उसने इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। अब तक इस एयरलाइंस पर जुर्माना लगाने की भी कोई जानकारी नहीं है।

मीडिया में प्राप्त जानकारी से पता लग रहा है कि विभिन्न सुरक्षा संबंधी मानकों को ध्यान में रखते हुए और पायलटों के उडान के घंटे निर्धारित करने के कारण इंडिगो के लिए फ्लाइट संचालन करना असंभव था। फिर भी इंडिगो को अपनी फ्लाइट्स की संख्या 14००0 से बढ़ाकर 15००0 करने की अनुमति दे दी। इन सब का परिणाम यह हुआ कि इंडिगो के पास पायलटों की संख्या अत्यंत कम हो गई। बदली परिस्थितियों में, इंडिगो ने आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पायलटों की समय पर भर्ती नहीं की। इसका असर फ्लाइट के संचालन पर पडना हो था। यह आश्चर्य की बात है कि अब सरकार ने पायलटों के उडान के घंटे नियमित करने वाला अपना आदेश इंडिगो कंपनी के लिए 1० फरवरी तक स्थाित कर दिया है। ऐसा करके क्या सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा को ताक पर नहीं रख दिया है? प्रधानमंत्री जी ने नारा तो “मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट” का दिया था लेकिन निजी कंपनियों को जिस प्रकार से मनमानी करने की खुली छूट दे दी गई है, उसे तो ‘मैक्सिमम गवर्नेंस’ के

स्थान पर ‘नो गवर्नेंस’ ही कह सकते हैं।

सरकार की अनुपस्थिति लगभग हर उस क्षेत्र में अनुभव की जा रही है जिससे नागरिक का जीवन प्रभावित होता है। वाहनों की संख्या में अनाप-शनाप वृद्धि से शहरों में पार्किंग का कोई स्थान नहीं बचा है और इसलिए सड़कों पर वाहन बेतरतीब खड़े रहते हैं, जिसके कारण प्रतिदिन सड़क हादसों में लोग पर रहे हैं। अतिरिक्त और भवन निर्माण के नियमों की अगवहेलना एक सामान्य बात हो गई है। जयपुर के मालवीय नगर में एक निर्माणधीन चार मंजिला भवन झुकने लगा और जनजीवन के लिए खतरा बन गया तो पता चला कि यह बिना अनुमति के बन रहा था। कैसी सरकार और कैसा शासन?

चलती बसों में आग लगने के कारण यात्रियों की मृत्यु होना, अस्पताल में शॉर्ट सर्किट के कारण हुई आग से मरीजों की मौत होना, यही सिद्ध करते हैं कि सरकार के लिए आम नागरिक के जीवन का कोई महत्व नहीं रह गया है। जब मैं यह संपादकीय लिख ही रहा हूँ तभी गोवा के नाइट क्लब में भयंकर आग लगने की खबर आई है। इसमें 25 लोग दम घुटने से मर गए क्योंकि उनके और जाने का एक ही दरवाजा था। स्पष्ट है, न सरकार को न शासन।

जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है उसके अधिकारियों का काम केवल व्यापारियों और आम जनता से अनधिकृत रूप से वसूली करना रह गया है। जनता का हित सरकार के लिए सबसे अंतिम प्राथमिकता बनकर रह गया है। जिस प्रकार से अस्पतालों में मुख्यमंत्री आरक्षण योजना लागू होने के बाद भी गरीब लोग अस्पताल में धक्के खा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि गवर्नमेंट नारा की कोई चीज नहीं है। लोकतांत्रिक कल्याणकारी सरकार का पहला दायित्व यही होता है कि वह जनता के हित को सर्वोपरि रखे, लेकिन जिस प्रकार के घटनाक्रम हम आजकल देख रहे हैं, उसको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि सरकार के लिए बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों का हित संरक्षण ही एकमात्र काम रह गया है। साधारण जनता को निजी कंपनियों के हवाले छोड़ दिया गया है। मेडिकल की पढाई करने वाले एक–एक छात्र से साल का एक करोड रुपया लिया जा रहा है। ऐसा करके क्या कभी कोई साधारण परिवार का व्यक्ति वर्तमान शासन व्यवस्था में एमबीबीएस या एम डी करने की सोच भी सकता है?

विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों अथवा अन्य सेवाओं के कर्मचारियों/ अधिकारियों को सुशासन पर प्रशिक्षण दिए जाने के बावजूद यदि हम गुड गवर्नेंस के बजाय ‘नो गवर्नेंस’ की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो यह चिंता की बात है। इस प्रकार की स्थिति में, जिनके पास अकूत धनराशि है या जो प्रभावशाली हैं, वे तो किसी भी प्रकार से अपना काम निश्चित लेंगे लेकिन साधारण नागरिक के पास तो प्रताड़ित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। उदाहरण के लिए, हाल ही में किए जा रहे एस आई आर में लगभग सभी सरकारी शिक्षकों की इयूटी लगा दी गई है और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढाई, जो वैसे ही खस्ता हाल है, अब बिल्कुल ही समाप्त हो गई है। सरकार के संरक्षण की आवश्यकता ही साधारण परिवार को सर्वाधिक होती है और दुर्भाग्य से वही शोषण का शिकार हो रहा है। सरकार अपने मूल दायित्व को तिलांजलि देकर केवल पूंजीपतियों के हित संरक्षण को उठी रहेगी तो वही स्थिति होगी जो अभी इंडिगो के प्रकरण में हुई है।

आज नागरिक प्रश्न पृष्ठ रहा है कि सरकार को उससे विभिन्न नामों से टैक्स वसूल करती है उससे उसे लाभ क्या हो रहा है ? सरकार न तो उसे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है न ही उसे निजी क्षेत्र के हाथों शोषित होने से बचा पा रही है। उसके बच्चे यदि पढाई नहीं कर सके, रहने के लिए अपना छोटा सा घर नहीं बना सके, अपने लिए कोई रोजगार नहीं ढूँढ सके, प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लोक होते चले जाएं तो उसे हम लोक कल्याणकारी राज्य का नागरिक कह पाएंगे ? सरकार को चाहिए था कि तेजी से निजीकरण करते समय एक प्रभावी नियामक व्यवस्था स्थापित करती। पैसे की ताकत के आगे सरकार के मंत्री और अधिकारी या तो लाचार हैं या अपने स्वार्थ के कारण उनके समक्ष नतमस्तक हो गए हैं। यह भी पता चला है कि इंडिगो कंपनी के मालिक राहुल भाटिया ने सप्ताधाारी दल को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 2० करोड रुपए दिए थे। यदि ऐसा नहीं है तो फिर अब तक नागरिक उड्डयन मंत्री और महानिदेशक डी जी सी ए को क्यों नहीं हटया गया है ?

साधारण जनता मिलावटी दूध पीने, मिलावटी सब्जियां, फल एवं खाद्य पदार्थ खाने और जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। वास्तव में सरकार होती तो मिलावट करने वालों को अब तक सजा मिल चुकी होती। न किसी को जेल हुई न किसी को गिरफ्तार किया गया।

मेरे जैसे साधारण नागरिक को तो केवल एक ही अपेक्षा है कि सरकार प्रभावी रूप से नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करे और नियंत्रण व्यवस्था में ऐसे लोगों को लगाए जो ईमानदारी से अपना काम करें, ताकि निजी संस्थाएं भी बनी रहें और किसी का शोषण भी व्यवस्था में न हो।

इंडिगो की हाल की घटनाक्रम से तो यह लगता है कि सरकार पूरे प्रकरण में अनुपस्थित ही रही है। अनुपस्थित सरकार जनता का भला नहीं कर सकती। जनता चाहती है कि सरकार उसके हित में काम करे। हम तो केवल आशा ही रख सकते हैं कि सरकार अब भी जागे और सुशासन नहीं तो कम से कम शासन तो उपलब्ध कराए। दुर्भाग्य से न्यायपालिका भी सरकार की निष्क्रियता का संज्ञान नहीं ले रही है और न सरकार को बाध्य कर रही है कि वह एक प्रभावी कार्यपालिका की भूमिका संविधान के अंतर्गत निभाए।

फिलहाल तो ऐसा लगता कि प्रधानमंत्री का “मैक्सिमम गवर्नेंस” का दावा ‘नो गवर्नेंस’ में परिवर्तित हो गया है।

–**अतिथि सम्पादक,**
राजेन्द्र भागवत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)



डॉ. लोकेश चंद्र शर्मा

राजस्थान विधानसभा म राष्ट्रीय गात वंदे मातरम् को समर्पित विशिष्ट, शोधपरक और आधुनिक स्वरूप वाली दीर्घा में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, स्वाधीनता के सांस्कृतिक प्रतीकों और राष्ट्रभक्ति की सामूहिक चैतना के ऐतिहासिक तथ्यों को नए स्वरूप में प्रस्तुत किया है। भारतीय लोकतंत्र की आत्मा से संवाद करती इस पहल से देश की विधान सभाओं में राजस्थान विधान सभा इस ऐतिहासिक उपलब्धि से विशिष्ट बन गई है। राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी की इस गौरवमयी सोच के साकार होने से विधान सभा का पवित्र परिसर शौर्य के भाव से आलोकित हो गया है। श्री देवनानी ने विधान सभा में भारतीय संविधान के 22 भागों के प्रारम्भ में प्रकाशित चित्रों की पृष्ठभूमि को समझाने के लिए संविधान दीर्घा और कारगिल वीरगणनाओं को समर्पित शौर्य वाटिका का भी निर्माण कराया है।

राजस्थान विधान सभा देश की पहली विधान सभा जहां वंदे मातरम् दीर्घा- देश की विधानसभाओं में राजस्थान



प्रो. वीर बहादुर सिंह

राजस्थान सरकार ने प्रदेश में पांच कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की, ये संस्थान, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और जोबनेर स्थानों पर संचालित हैं। ये सभी विश्वविद्यालय विधान सभा में उपयुक्त विधान पेश कर और गजट में नोटिफिकेशन उपरांत स्थापित किये गए हैं। सभी के विधान भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली के मॉडल पर अनुसृत बनाये गए हैं। एक प्रकार से ये एन्ट और स्टूट्रेस सम्बन्धित विश्वविद्यालय के लिए संविधान का उद्देश्य पूरा करते हैं जिनके प्रोविशंस के अनुसार विश्वविद्यालय अपने सभी क्रिया कलापों को अंजाम देते हैं।

इसके ही प्रावधानों के अंतर्गत कुछ बड़ी समितियाँ गठित होती हैं जिनमें प्रबंध मंडल सर्वोच्च औरअकादमिक काँसिल प्रमुख हैं। फिर विधान के ही अंतर्गत बोर्ड ऑफ स्टडीज अथवा फैकल्टी होती है। एक फैकल्टी एक संकाय के सभी अकादमिक और नॉन अकादमिक कार्य देखती है। वर्तमान स्थिति में कृषि संकाय, कृषि अभियांत्रिकी संकाय, होम साइंस संकाय, डेरी व् फूड टेक्नोलॉजी संकाय और फिशरीज लिमनोलोजी संकाय और बागवानी व् फारेस्ट्री संकाय इन संस्थानों में गठित किये हुए हैं। प्रत्येक मुख्य संकाय का एक महाविद्यालय है जैसे कृषि महाविद्यालय, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, होम साइंस महाविद्यालय, डेरी व् खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय आदि जहाँ शिक्षा और अभिस्नातक स्तरों को शिक्षा देने का प्रावधान है सभी महाविध्यालयों में अनेक विषय अनुसार विभाग होते हैं।जिनमें प्रत्येक

का एक विभागाध्यक्ष होता है।

कुछ अपवादों को छोडकर इन सभी पाठ्यक्रमों के अलावा अनुसन्धान या पीएचडी पाठ्यक्रम भी कुछ विषयों में उपलब्ध हैं। ये सभी पाठ्यक्रम नॉलेज विस्तार के कारण विषय सामग्री से बहुत प्रचुर हैं, जिन्हें पढाने के लिए वांछित वैज्ञानिक या अध्यापकों की जरूरत होती है। ये वैज्ञानिक पीएचडी तो होते ही हैं अपने ही विषय के किसी एक या दो पक्षों में विशेषयता रखते हैं जिसे वे अधिस्नातक और पीएचडी छात्रों को पढाने भी हैं और किसी एक समस्या पर शोध भी करवाते हैं। शोध भी अपने में एक जटिल प्रक्रिया है, जिसे आखिर तक अंजाम तक पहुँचाने में शोधार्थी व् वैज्ञानिक को सतत परिश्रम और समय लगना होता है।

उपरोक्त वर्णित डिग्री प्रोग्राम और

राशिफल मंगलवार 9 दिसम्बर, 2025



पंडित अनिल शर्मा

से सिंह राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-कर्क मंगल-धनु, बुध-वृश्चिक, गुरू-मिथुन, शुक्र-वृश्चिक, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से रात्रि २:23 तक

है। रवियोग और कुमार योग रात्रि २:२3 से आरम्भ होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:44 से 11:०1 तक, लाभ-अमृत 11:५१ से 1:37 तक, शुभ 2:54 से 4:12 तक।

राहूकाल: 1:3० से 3:०0 तक। **सूर्योदय 7:08, सूर्यास्त 5:29 तक**

विधानसभा अब उन विरल संस्थानों में शामिल हो गई है जहाँ वंदे मातरम् पर आधारित एक पूर्ण शोधपरक गैलरी का निर्माण हुआ है। राष्ट्र गीत के एक सौ पचास वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में तैयार इस दीर्घा में 37 पैनों के माध्यम से वंदे मातरम् की रचना, इतिहास, संदर्भ और स्वतंत्रता संग्राम में उसकी भूमिका को क्रमबद्ध रूप से सजाया गया है। वंदे मातरम्, मातृभूमि के प्रति समर्पण, औपनिवेशिक दमन के विरुद्ध प्रतिरोध और स्वाधीनता की सामूहिक चेतना का स्वरूप है। स्वदेशी आंदोलन के दौर में यह गीत जनसभाओं और आंदोलनों का प्रेरक केंद्र बनकर राष्ट्रीय भावता को संगठित करता रहा और उसी चिरंतन स्वरूप को यह दीर्घा आधुनिक माध्यमों में पुनर्जीवित कर रही है।

नए विमर्श और आधुनिकता के साथ आमजन को समर्पित- राजस्थान विधानसभा परिसर स्थित राजनैतिक आख्यान संग्रहालय में यह नई दीर्घा स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को नए विमर्श और आधुनिक प्रस्तुति के साथ आमजन तक पहुँचाती है। वंदे मातरम् का भावपूर्ण संगीत, दुर्लभ दस्तावेजों, वीडियो सामग्री और उस युग के सांस्कृतिक-राजनैतिक परिवेश का सजीव प्रदर्शन आगतुकों को उस समय की अनुभूति से जोड़ता है। मातृभूमि के प्रति प्रेम, कर्तव्य और संविधान के प्रति निष्ठा को इस दीर्घा का मूल केंद्र माना गया है, जो इसे मात्र प्रदर्शनी नहीं बल्कि प्रेरणा का स्थायी स्रोत बनाता है।

जीवंत ज्ञान केन्द्र- 1८७5 में अक्षय नवमी के दिन बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा मुर्शिदाबाद के लालगोला में रचे गए मूल गीत की

पांडुलिपि, संस्कृतनिष्ठ बंगाली पाठ, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े दुर्लभ फोटोग्राफ, क्रांतिकारियों के संस्मरण, पत्र, भाषण और तत्कालीन सांस्कृतिक वातावरण की झलक इस दीर्घा को विशेष बनाती है। युवा वर्ग, शोधार्थियों और इतिहास में रुचि रखने वाले नागरिकों के लिए यह दीर्घा एक जीवंत ज्ञान केन्द्र के रूप में उभर रही है। राष्ट्रीय चेतना को आलोकित करने वाली राजस्थान विधान सभा ने नई पीढ़ी के लिए कर्तव्यों और अधिकारों के संतुलन के साथ राष्ट्र-प्रथम की भावना को सर्वोपरि बनाये रखने का वातावरण निर्मित किया है।

स्पीकर श्री वासुदेव देवनानी की इस पूरी पहल का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि राजस्थान विधानसभा ने इतिहास को स्थिर रूप में नहीं, बल्कि जीवंत एवं संवादमय रूप में प्रस्तुत किया है। संग्रहालय का यह विस्तार ऐसी सीध को दर्शाता है जिसमें राजनीति केवल नीतियों और बहसों तक सीमित न रहकर संस्कृति, इतिहास और नागरिक चेतना को भी समान महत्व देता है। इतिहास को महसूस कराने वाली दीर्घा वंदे मातरम् दीर्घा- वंदे मातरम इतिहास, संस्कृति और संवैधानिक आदर्शों का पेशा विशिष्ट संगम बनकर उभर रही है, जो भारतीय लोकतंत्र की गहराई और राष्ट्रीय चेतना की व्यापकता को नई पीढ़ियों तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण माध्यम सिद्ध होगा। राजस्थान विधानसभा में वंदे मातरम् दीर्घा केवल अतीत का अभिलेख नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय पहचान को जोड़ने वाला समकालीन कार्य है। डिजिटल इंटरैक्टिव पैनों और ऐतिहासिक दस्तावेजों के संयोजन ने इसे पारंपरिक

राज्य सरकार के विघटनकारी रव्ये से कृषि विश्वविद्यालयों के एक्ट और स्टैचूट्स गैरजरूरी व अर्थहीन

का एक विभागाध्यक्ष होता है।

कुछ अपवादों को छोडकर इन सभी पाठ्यक्रमों के अलावा अनुसन्धान या पीएचडी पाठ्यक्रम भी कुछ विषयों में उपलब्ध हैं। ये सभी पाठ्यक्रम नॉलेज विस्तार के कारण विषय सामग्री से बहुत प्रचुर हैं, जिन्हें पढाने के लिए वांछित वैज्ञानिक या अध्यापकों की जरूरत होती है। ये वैज्ञानिक पीएचडी तो होते ही हैं अपने ही विषय के किसी एक या दो पक्षों में विशेषयता रखते हैं जिसे वे अधिस्नातक और पीएचडी छात्रों को पढाने भी हैं और किसी एक समस्या पर शोध भी करवाते हैं। शोध भी अपने में एक जटिल प्रक्रिया है, जिसे आखिर तक अंजाम तक पहुँचाने में शोधार्थी व् वैज्ञानिक को सतत परिश्रम और समय लगना होता है।

उपरोक्त वर्णित डिग्री प्रोग्राम और सम्बन्धित महाविद्यालय जहाँ वो डिग्री प्रोग्राम संचालित होते हैं, को भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद नई दिल्ली से अनुमोदित अथवा प्रत्यापित या प्रामाणिक होना आवश्यक होता है इसके लिए सम्बन्धित संस्था से निवेदन मिलते हैं। परिषद एक विशेषज्ञों की समिति गठित कर देती है जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय का निरीक्षण कर और सभी दृष्टिओं से संतुष्ट होकर शिक्षा या डिग्री प्रोग्राम अथवा महाविद्यालय को जारी गई अनुसंश प्रदान कर देती है। इस अनुसंश के बाद ही वह प्रोग्राम पूरे देश में मान्य हो जाता है और कौंसिल से विभिन्न कार्यों के लिए आर्थिक सहायता के लिए भी उपयुक्त हो जाता है।

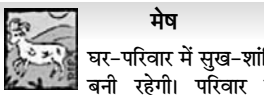
बिना इस मान्यता के प्रदान की गई डिग्री देश के किसी भी संस्थान में आगे प्रवेश और रोजगार के लिए मान्य नहीं होती है। अक्रेडिटेशन समिति उपस्थित फैकल्टी व् उनकी विशेषयता, प्रयोगशालाएँ और प्रायोगिक कक्षाओं के लिए समुचित उपकरण की मौजूदगी, वांछित प्रयोगशाला सहायक और समुचित बजट प्रावधानों के होते हुए अक्रेडिटेशन के लिए अनुसंश कर देती है

उपरोक्त सभी कारकों का समुचित स्तरों का होने पर ही समिति संतुष्ट होकर प्रामाणिकता प्रदान करे की अनुसंश करती है। स्नातक विषय तो एक अनुभवरहित फैकल्टी पढा सकती है

लेकिन अधिस्नातक और पीएचडी विषय पढाने के लिए अध्यापक अथवा फैकल्टी का पोस्टग्रेजुएट कौंसिल से अनुमोदन आवश्यक होता है। बिना अनुमोदित प्राप्त व्यक्ति अधिस्नातक और पीएचडी के विषय पढाने के लिए अनयोग्य माना जाता है। इस लेख को पढने के बाद छात्र भी आंकलन कर सकते हैं कि वे कैसा विषय पढ रहे हैं और उसे पढाने वाला किस स्तर का है ? माँ बाप का पैसा उचित जगह ही खर्च हो तभी छात्र को उस शिक्षा का लाभ हो सकता है। पीएचडी पढाने और थीसिस (रिसर्च) गाइड के लिए सुपरवायजर अथवा अध्यापक को उच्च कोटि का विषय ज्ञान और रिसर्च का वांछित स्तर का अनुभव रखना जरूरी है। यदि गाइड में वांछित अनुभव की कमी है तो वह संतोष स्तर की थीसिस छात्र को नहीं करा सकता। ऐसे में चालाकी से कुछ छात्र लाइब्रेरी से मिलती जुलती सूच की किसी थीसिस से कुछ भागों की नकल कर लेते हैं जो एक प्रकार से नकल करने के समान है।

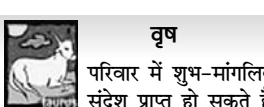
कृषि महा विद्यालओं और विश्व विद्यालओं में सतत अनुसन्धान स्वरूप द्रुत गति से बढ़ती विषय सामग्री को पढाई में निरंतर समावेश भी कृषि शिक्षा में जरूरी है अन्यथा हाल ही में उपजी जानकारी से छात्र वर्चित रह जायेंगे। इसलिए यूनिवर्सिटी के एन्ट और स्टूट्स में विषय वाा समिति ऑफ़ कोर्सेस भी गठित होती है जिसमें विभाग के सभी स्तियार अध्यापक और विश्वविद्यालय से बाहर के एक या दो आमंत्रित विशेषज्ञ नामित किये जाते हैं। इनकी उपस्थिति से किसी अन्य विशेषज्ञ के ज्ञान का लाभ तो मिलता ही है विषय अपडेट करने में, अन्य संस्थानों में स्थिति और स्तरों की सूचना भी मिल जाती है।

उपरोक्त सभी समितियों की निर्धारित अंतराल पर बैठक आहूत की जाती है। विश्व विद्यालय में यदि विषय के अंतर्गत वांछित फैकल्टी नहीं हो तो उपरोक्त समितियों का गठन संभव नहीं। सरकार में बैठे प्रशासनिक अधिकारिओं ने अपनी सोची समझी रणनीति के अनुसार रिक्त पदों पर चयन करने की परमिशन को संदेव टाला है। फलस्वरूप विभाग तो खाली है ही, महाविद्यालयों



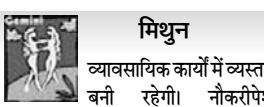
मेष

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।



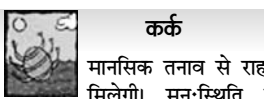
वृष

परिवार में शुभ-मांगलिक संदेश प्राप्त हो सकते हैं। परिवार में परिवर्जनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



मिथुन

व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है।



कर्क

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनासुचारु बनने लगेंगे।



संग्रहालयों की सीमाओं से आगे पहुँचा दिया है। इसे देखने वाले स्वतंत्रता आंदोलन की भावनाओं संघर्षों और राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा को अनुभव करते हैं। यह पहल आने वाले वर्षों में न केवल शोधार्थियों के लिए बल्कि उन युवाओं के लिए भी अत्यंत मूल्यवान साबित होगी जो इतिहास को केवल पढना नहीं, बल्कि उसे महसूस करना चाहते हैं।

करोड़ों भारतीयों की सामूहिक स्मृति का प्रतिबिम्ब- वंदे मातरम् दीर्घा राष्ट्रगीत के इतिहास को समेटे हुए है। यह भारत की सांस्कृतिक चेतना को जन भाषा में प्रस्तुत करती है। दीर्घा के प्रत्येक पैनल में स्वतंत्रता संग्राम के दृश्य, आंदोलनकारी ऊर्जा के अंश और राष्ट्रनिर्माण में काला-साहित्य की भूमिका के अध्याय सजीव हो उठे हैं। यह दीर्घा उन करोड़ों भारतीयों की सामूहिक

स्मृति का प्रतिबिंब है जिन्होंने अंग्रेजी शासन का प्रतिरोध करते हुए वंदे मातरम् की अपनी आवाज का आधार बनाया था। आधुनिक भारत की युवा पीढ़ी जब इस दीर्घा में प्रवेश करती है, तो वह केवल इतिहास नहीं देखती वह अपने भीतर राष्ट्रभावना की एक नई समझ का जन्म अनुभव करती है।

लोक संस्कृति पथ - राजस्थान विधान सभा के राजनैतिक आख्यान संग्रहालय के प्रवेश पथ को कला, संस्कृति, लोकनृत्य, पारंपरिक प्रतीक और ऐतिहासिक घरोहरों के भिंति चित्रों से उकेरा गया है। यह लोकक संस्कृति से परिचय कराने वाला पथ बन गया है।

–**डॉ. लोकेश चंद्र शर्मा,**
उप निदेशक जनसंपर्क, राजस्थान विधानसभा, जयपुर

करोड़ों भारतीयों की सामूहिक स्मृति का प्रतिबिम्ब- वंदे मातरम् दीर्घा राष्ट्रगीत के इतिहास को समेटे हुए है। यह भारत की सांस्कृतिक चेतना को जन भाषा में प्रस्तुत करती है। दीर्घा के प्रत्येक पैनल में स्वतंत्रता संग्राम के दृश्य, आंदोलनकारी ऊर्जा के अंश और राष्ट्रनिर्माण में काला-साहित्य की भूमिका के अध्याय सजीव हो उठे हैं। यह दीर्घा उन करोड़ों भारतीयों की सामूहिक स्मृति का प्रतिबिंब है जिन्होंने अंग्रेजी शासन का प्रतिरोध करते हुए वंदे मातरम् की अपनी आवाज का आधार बनाया था। आधुनिक भारत की युवा पीढ़ी जब इस दीर्घा में प्रवेश करती है, तो वह केवल इतिहास नहीं देखती वह अपने भीतर राष्ट्रभावना की एक नई समझ का जन्म अनुभव करती है।

लोक संस्कृति पथ - राजस्थान विधान सभा के राजनैतिक आख्यान संग्रहालय के प्रवेश पथ को कला, संस्कृति, लोकनृत्य, पारंपरिक प्रतीक और ऐतिहासिक घरोहरों के भिंति चित्रों से उकेरा गया है। यह लोकक संस्कृति से परिचय कराने वाला पथ बन गया है।

करोड़ों भारतीयों की सामूहिक स्मृति का प्रतिबिम्ब- वंदे मातरम् दीर्घा राष्ट्रगीत के इतिहास को समेटे हुए है। यह भारत की सांस्कृतिक चेतना को जन भाषा में प्रस्तुत करती है। दीर्घा के प्रत्येक पैनल में स्वतंत्रता संग्राम के दृश्य, आंदोलनकारी ऊर्जा के अंश और राष्ट्रनिर्माण में काला-साहित्य की भूमिका के अध्याय सजीव हो उठे हैं। यह दीर्घा उन करोड़ों भारतीयों की सामूहिक स्मृति का प्रतिबिंब है जिन्होंने अंग्रेजी शासन का प्रतिरोध करते हुए वंदे मातरम् की अपनी आवाज का आधार बनाया था। आधुनिक भारत की युवा पीढ़ी जब इस दीर्घा में प्रवेश करती है, तो वह केवल इतिहास नहीं देखती वह अपने भीतर राष्ट्रभावना की एक नई समझ का जन्म अनुभव करती है।

लोक संस्कृति पथ - राजस्थान विधान सभा के राजनैतिक आख्यान संग्रहालय के प्रवेश पथ को कला, संस्कृति, लोकनृत्य, पारंपरिक प्रतीक और ऐतिहासिक घरोहरों के भिंति चित्रों से उकेरा गया है। यह लोकक संस्कृति से परिचय कराने वाला पथ बन गया है।

करोड़ों भारतीयों की सामूहिक स्मृति का प्रतिबिम्ब- वंदे मातरम् दीर्घा राष्ट्रगीत के इतिहास को समेटे हुए है। यह भारत की सांस्कृतिक चेतना को जन भाषा में प्रस्तुत करती है। दीर्घा के प्रत्येक पैनल में स्वतंत्रता संग्राम के दृश्य, आंदोलनकारी ऊर्जा के अंश और राष्ट्रनिर्माण में काला-साहित्य की भूमिका के अध्याय सजीव हो उठे हैं। यह दीर्घा उन करोड़ों भारतीयों की सामूहिक स्मृति का प्रतिबिंब है जिन्होंने अंग्रेजी शासन का प्रतिरोध करते हुए वंदे मातरम् की अपनी आवाज का आधार बनाया था। आधुनिक भारत की युवा पीढ़ी जब इस दीर्घा में प्र



हादसे में महिला सहित तीन लोगों की मौत

निजी बस बाइक को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलटी खाई

जयपुर/हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना इलाके के मानकसर में सोमवार सुबह एक निजी बस बाइक को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक महिला सहित तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चौदह यात्री घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। बस में सवार घायल यात्रियों को संगरिया पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। इनमें से 3 घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रैंफर किया गया है।

हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक हरी शंकर ने बताया कि यह हादसा सोमवार सुबह तब हुआ जब हनुमानगढ़ से डबवाली की ओर जा रही एक निजी बस एक बाइक से टकरा गई। इस टक्कर के बाद पोल से टकराकर बस बेकाबू होकर पलट गई।

इस हादसे में बाइक सवार नगराना निवासी लखवेंदर सिंह (40) और



हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना इलाके के मानकसर में सोमवार सुबह एक निजी बस पलटने के बाद मौके पर काफी भीड़ एकत्रित हो गई।

बग्गा सिंह (28) की मौके पर ही मौत हो गई। बस पलटने से बस में सवार गंभीर रूप से घायल हनुमानगढ़ टाउन की नई आबादी निवासी महिला कमलदीप कौर (35) ने भी दम तोड़

दिया। वहीं रामपुर (यूपी) निवासी अनवर अली (45), श्रीकरणपुर (बाई 9) निवासी (62), सुरेशिया निवासी सुरेंद्र कुमार (45), सुरेशिया आनंद पांडे (40), कणवाली रावतसर

■ **बस में सवार घायल यात्रियों को संगरिया पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया।**

निवासी कालुराम (47) (जो वर्तमान में संगरिया में हेड कांस्टेबल है) और श्रीगंगानगर की पुष्पा (40) घायल हो गए। इनमें से तीन घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। एसपी हरी शंकर ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि बाइक सवार युवक नगराना गांव के रहने वाले थे और घटनास्थल के पास एक होटल से निकले थे। पुलिस ने बस को हटवाकर यातायात सुचारू करवाया। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

फैक्ट्री में आग से नुकसान

भीलवाड़ा। सोमवार तड़के स्वरूपगंज स्थित रीको ग्रोथ सेंटर की नीता एंटरप्राइजेज गता फैक्ट्री में अचानक लगी भीषण आग ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। घने धुएं के गुबार ने कुछ ही मिनटों में फैक्ट्री परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। अल सुबह काम पर मौजूद मजदूरों ने स्थिति बिगड़ती देख तुरंत हमीरागढ़ थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थानाप्रभारी सुनील बेड़ा मौके पर पहुंचे और हालात गंभीर देखकर तत्काल अग्निशमन विभाग को बुलाया। दमकल वाहनों ने पहुंचकर करीब डेढ़ घंटे की कड़ी शेषकत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस व अग्निशमन दल ने समय रहते आग की लपटों को दूसरे शेड तक फैलने से रोका।

हथियारों के साथ 50 हजार के इनामी सहित दो बदमाश पकड़े

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर कमिश्नरेट की महामंदिर पुलिस ने अवैध हथियारों को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने उदयपुर के हिस्ट्रीशीटर को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया है। इसमें एक बदमाश पचास हजार रुपए का इनामी है। आरोपी एक हिस्ट्रीशीटर की मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे। आरोपियों के कब्जे से तीन पिस्टल, दो कारतूस और एक क्रेटा कार भी जब्त की गई है। पुलिस अब उनसे हथियारों को लेकर पूछताछ कर रही है।

पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश ने बताया कि कमिश्नरेट पुलिस संगठित अपराधियों को चिन्हित करके कार्रवाई कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधिक तत्व यहां घूम रहे हैं। डीसीपी (पूर्व) पीडी निर्या की मॉनिटरिंग में इस सूचना को बीट कांस्टेबल प्रकाश ने डेवलप किया। इसके आधार पर पचास हजार के इनामी बदमाश उदयपुर निवासी हिस्ट्रीशीटर नरेश वाल्मीकि और जैसलमेर निवासी अमन वाल्मीकि को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से तीन पिस्टल और

- **तीन पिस्टल व दो कारतूस बरामद**
- **क्रेटा कार जब्त, हिस्ट्रीशीटर को मारने के लिए कर रहे थे प्लानिंग**

दो कारतूस बरामद हुए। आरोपी नरेश के खिलाफ अलग-अलग थानों में करीब 37 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं अमन के खिलाफ छह मुकदमे दर्ज हैं। इनके खिलाफ 111 की धारा लगाई गई है। जो संगठित अपराधियों के खिलाफ लगाई जाती है। दोनों को भदवासिया इलाके से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नरेश के खिलाफ उदयपुर पुलिस ने 50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। आरोपी इसके चलते फरार चल रहा था। आरोपी आने वाले समय में उदयपुर के ही हार्डकोर अपराधी प्रवीण कसेटा की हत्या की साजिश रच रहा था। प्रवीण अंबामाता थाने का हिस्ट्रीशीटर है।

बिजली के तार गिरने से किसान की मौत

जोधपुर, (कासं)। देवू थाना क्षेत्र के पुनियां की ढाणी गोविंदपुरा गांव में बिजली के तार गिरने से एक किसान की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से झुलस गया। यह घटना 11 हजार केवी की बिजली लाइन के जर्जर पोल गिरने के कारण हुई। जानकारी के अनुसार 11 हजार केवी की विद्युत लाइन पर लगे सात जर्जर पोल अचानक गिर गए। इससे 11 केवी के तार पास से गुजर रही एलटी लाइन पर गिरे, जिससे एक ट्रांसफार्मर भी नीचे आ गया। एलटी लाइन में विद्युत आपूर्ति चालू होने के कारण दो किसान इसकी चपेट में आ गए। हादसे में खेताराम मेघवाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, चेनाराम गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे देवू अस्पताल से जोधपुर रेफर किया गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि देवू डिस्कॉम को इन जर्जर बिजली के पोलों के बारे में पहले ही सूचित किया गया था। ग्रामीणों ने चेतावनी दी थी कि ये पोल कभी भी किसी की जान ले सकते हैं, लेकिन डिस्कॉम के अधिकारियों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की।

मुख्यमंत्री ने राजस्व से संबंधित विभागों की समीक्षा की

राज्य के सर्वांगीण विकास में राजस्व की भूमिका अहम, वृद्धि के लिए बनाएं लक्ष्य आधारित कार्य योजना

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास और सभी वर्गों के कल्याण के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इस दिशा में विभिन्न विकास परियोजनाएं और जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने और जनकल्याणकारी योजनाओं के निर्बाध संचालन में राजस्व अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी समर्पित होकर कार्य करें। शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आबकारी, परिवहन, कॉमर्शियल टैक्स तथा पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे। बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 लाख 69 हजार 627 करोड़ रुपये के राजस्व अर्जन का लक्ष्य रखा गया था। इसे हासिल करने के क्रम में नवम्बर माह तक कुल 84 हजार 746



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की।

करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आगामी तिमाही में राजस्व वृद्धि के लिए लक्ष्य आधारित कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। जीएसटी की दरों में कमी का लाभ उपभोक्ता को मिलना हो सुनिश्चित। शर्मा ने कॉमर्शियल टैक्स विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा किए गए जीएसटी

सुधारों से देश और प्रदेश के आमजन को काफी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जीएसटी की दरों में की गई कमी का सीधा लाभ उपभोक्ता तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने फर्जी करदाताओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि कर चोरी रोकने और पारदर्शी कर व्यवस्था लागू करने के लिए सख्त निगरानी तंत्र

विकसित किया जाए। सार्वजनिक परिवहन हेतु नई बसों के हो परामित जारी मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सार्वजनिक परिवहन हेतु नई बसों के अधिक से अधिक परामित जारी किए जाएं जिससे आमजन को आवागमन में सुविधा होने के साथ ही, राज्य सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति हो।

‘विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाये’

जयपुर। ऊर्जा मंत्री हिरालाल नागर ने निर्देश दिए हैं कि ब्लॉक ऑवर सप्लाई को मंटेन कर रबी सीजन में कृषि एवं अन्य उपभोक्ताओं को व्यवधान रहित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही सप्लाई को प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए मुख्यालय से निचले स्तर तक अधिकारी भेजे जाएं, जो कि ट्रिपिंग वाले गिड सब स्टेशनों तथा फीडर को चिन्हित कर उनमें लोड प्रबंधन की बेहतर प्लानिंग करें। नागर रबी सीजन में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्थाओं की मॉलवार को विद्युत भवन में समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान निर्देश दिए कि पीक ऑवर्स को डिमांड को पूरा करने के लिए बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। साथ ही प्रसारण निगम के स्तर पर भी बढ़े हुए लोड के अनुरूप पावर ट्रांसफार्मर्स की क्षमता वृद्धि के उपाय अभी से कर लिए जाएं। बैटक में प्रमुख शासन सचिव (ऊर्जा) अजिताभ शर्मा ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं तथा आरडीएसएस के अन्तर्गत कृषि एवं गैर कृषि फीडर सेग्रोगेशन कार्य को गति देने के निर्देश दिए। चेयरमैन डिस्कॉम्स आरती डोगरा ने मांग एवं इसके अनुरूप वितरण निगमों द्वारा की जा रही आपूर्ति की जानकारी दी। बैठक में ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध निदेशक ओम कसेरा तथा उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक देवेन्द्र श्रृंगी ने विद्युत उपलब्धता के बारे में बताया।

दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जाने वाली 6 फ्लाइट कैसिल

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस का शेड्यूल लगातार गड़बड़ाया हुआ है। इंडिगो की आज छह फ्लाइट कैसिल की गई है। ये फ्लाइट्स दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद के लिए जोधपुर से जाने वाली थीं। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक जोधपुर से तीन फ्लाइट हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली शहरों में जाती हैं। यहां से वापस इन शहरों के लिए जाती हैं।

इससे पहले रविवार को भी एयरपोर्ट से चार आने वाली और जाने वाली फ्लाइट को कैसिल किया गया था। हालांकि यहां पर रविवार को एयरपोर्ट पर फ्लाइट का संचालन नियमित हो गया था।

बीकानेर मंडी से हर रोज करीब 40 लाख बोरी मूंगफली गुजरात के व्यापारी खरीद रहे

- **गुजरात में बारिश की वजह से खराबा हुआ**
- **यूरोप और थाईलैंड तक होती है सप्लाई**

बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से खेतों में काफी पानी भर गया था। जमीन पथरीली होने के कारण वहां पानी फसल के ऊपर ही रहा, जिससे फसल खराब हुआ। ऐसे में इस बार दाना काफी छोटा और गौला निकला। लेकिन, उसकी तुलना में इस बार बीकानेर में गुजरात जैसी फसल हुई है। यहां इस बार दाना बड़ा और सुखा है। ऐसे में वहां के प्रोसेसिंग यूनिट और व्यापारियों में राजस्थान में होने वाली मूंगफली की डिमांड में अचानक बढ़ोतरी आई है। बीकानेर मंडी में रोजाना डेढ़ लाख

बोरी पहुंच रही है। कृषि मंडी के अधिकारियों के अनुसार इस बार 2 करोड़ क्विंटल बोरी इस बार बीकानेर की मंडी में आएगी। गुजरात में इतनी डिमांड बढ़ चुकी है कि रोजाना बीकानेर मंडी से हर रोज करीब 40 लाख बोरी गुजरात के व्यापारी खरीद रहे हैं। वहीं पिछले पांच वर्षों में बीकानेर में मूंगफली का उत्पादन में लगातार बढ़ ता जा रहा है। इसका अंकड़ा देखे तो लगातार दूसरी बार सबसे ज्यादा 8 लाख 70 हजार मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। ये ही कारण है कि इस बार भी बीकानेर की मंडी पूरी तरह मूंगफली से अटी पड़ी है। हर रोज डेढ़ लाख बोरी मंडी पहुंच रही है। मूंगफली की बढ़ती डिमांड की वजह से इस बार भाव भी बढ़े हैं। पिछली साल की तुलना में प्रति क्विंटल 500 रुपए का मुनाफा हो रहा है। इस बार मूंगफली 5500 से 6500 रुपए क्विंटल के आस-पास बिक रही है।

तीन दोषियों को कारावास

कोटा। अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी के करीब साढ़े पांच वर्ष पुराने मामले में एनडीपीएस न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी के तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए दस-दस वर्ष के कारावास साथ ही 1,00,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निम्बय ने बताया कि 18 जनवरी 2020 को थानाधिकारी थाना कुन्हाड़ी कोटा शहर ने नाकाबंदी के दौरान एक कार को डिटेन किया, जिसमें तीन जने बैठे हुए थे। कार में पीछे की सीट पर बैड़े हुए दोनो शख्सों के बीच में एक काले रंग का बैग रखा हुआ था। पुलिस टीम ने संदेह होने पर बैग की तलाशी ली तो बैग में से अवैध मादक पदार्थ 21 किलो गांजा बरामद किया।

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड		दिनांक - 03/12/2025
ई-निविदा सूचना	कार्य का विवरण	
निविदा संख्या एवं तिथि: F/9(141/C2/2022)-2025-18 Dated 03.12.2025 UBN No. MML2526GL0B00113	कंसनगढ़ मालासुख लिमिटेड माईन्स गांव-मालासुख एहली-जायल नागर में एक 11 ¹ / ₄ x3 केबी न्यूटल घाटडिग रिफ़ेक्टर (एनडीआर) की आपूर्ति, स्थापना, कमीशन और परीक्षण (निविदा दस्तावेजों में एन्क्लचर्ड सरी)। अनुमानित मूल्य (₹) 10.40 लाख, पंरोहर राशि (₹) ~ 20,800 /- , निविदा राशि ~ 1180 /- अदस्तावेजों में एन सी टी राशि। ई-निविदा प्रक्रिया शुरू करने के 500/- का डी डी, जो कि एम डी, आर.आई.एस.एल, जयपुर के नाम देना हो।	
उपरोक्त निविदा की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.sppp.raajasthan.gov.in अथवा प्रबंधक (सांख्यिकी-अनुबंध) से उपरोक्त पते पर सम्पर्क करें। raj.raj@raj.nic.in पर भी देखे जा सकते हैं।	www.sppp.raajasthan.gov.in अथवा प्रबंधक (सांख्यिकी-अनुबंध) से उपरोक्त पते पर सम्पर्क करें। raj.raj@raj.nic.in पर भी देखे जा सकते हैं।	अनुमानित मूल्य (₹) 10.40 लाख, पंरोहर राशि (₹) ~ 20,800 /- , निविदा राशि ~ 1180 /- अदस्तावेजों में एन सी टी राशि। ई-निविदा प्रक्रिया शुरू करने के 500/- का डी डी, जो कि एम डी, आर.आई.एस.एल, जयपुर के नाम देना हो।

OFFICE OF MEMBER SECRETARY, RAJASTHAN MEDICARE RELIEF SOCIETY SUPER SPECIALITY HOSPITAL, UDAIPUR		Date: 01.12.2025
No. RMRS/2025-26630		
Notice inviting bid		
Bids for various items of subject matters of procurement are invited from interested bidders upto 23.12.2025, 10.00 AM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal http://sppp.raajasthan.gov.in of the state.		
UBN NO. 1.MCU2526GLRC00307. The approximate value of the procurement is Rs. 20 lakh.		
UBN NO. 2.MCU2526GLRC00308. The approximate value of the procurement is Rs. 30 lakh.		
Member Secretary Rajasthan Medicare Relief Society SSH, Udaipur		
DIPR/C/17962/2025		

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जन स.अभि.विभाग, वृत्त प्रतापगढ़ E-Mail: secircle_pra.phed@rajasthan.gov.in		दिनांक-02.12.2025
क्रमांक- अअ/प्रताप/निविदा/2025-26/2262-2267		
ई-निविदा सूचना		
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्नहस्ताक्षरकों द्वारा सक्षम श्रेणी में मान्यता प्राप्त पंजीकृत संबद्धों को जिला प्रतापगढ़ के कार्या हेतु ऑनलाईन निविदा सं. 09-10/2025-26 आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित अन्य सभी विस्तृत विवरण मग निम्न लिंकियों के http://eproc.raajasthan.gov.in , www.sppp.raj.nic.in पर भी देखे जा सकते हैं।		
UBN NO. AS follows- UBT-9. PHE2526WSOB09300, NIT-10-PHE2526WSRC09301		
(शिवदयाल मीना) अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग वृत्त-प्रतापगढ़ (राज.)		
DIPR/C/17987/2025		

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर		दिनांक- 08.12.2025
क्रमांक- बि. सं. 12/Exam/Inspector(G&B)/RPSC/EP-1/2025-26		
आयोग द्वारा अवरजाना एवं बीयनर विभाग निगम के लिए राजस्थान सरकारका तथा अजमेर नरेशिक और बरखाना निरिक्षक (रखाना) सेवा निगम, 1958 के अन्तर्गत निरिक्षक, अवरजाना एवं बीयनर (Inspector of Factories & Boilers) के 12 पदों तथा निरिक्षक, अवरखाना (रखाना) (Inspector of Factories & Boilers) के 01 पद पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। शैक्षिक योग्यता आदर्श प्रक्रिया व अन्य विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी उक्त पदों हेतु आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन का अवलोकन करें। उक्त पदों हेतु आयु सीमा, आवेदन अर्जाएं व अन्य विवरण निम्नानुसार हैं-		
आयु सीमा	दिनांक 01.01.2027 को न्यूनतम 23 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए।	
आवेदन अर्जा	दिनांक 14.12.2025 से दिनांक 22.01.2026 तक 12.00 बजे तक	
परीक्षा का स्थान व माह	परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में व्यासमय सूचित कर दिया जायेगा।	
अन्य विवरण व सूचना परीक्षा से संबंधित अन्य विवरण व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन एवं संश्लिप्त सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से करें।। इसके अतिरिक्त अन्य परीक्षा के संबंध में सहाय-सम्पन्न पर जगदी राजनगरी का अवलोकन आयोग की वेबसाइट http://www.sppp.raajasthan.gov.in पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मांग विवेचन/पत्र/संपर्क/संपर्क हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अवकाश दर्ज करें- 0145-2653212 एवं 2653200 पर सर्वेक किया जा सकता है। संपन्न पर व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को संबोधित किया जाए। (रामनिवास मेहता) सचिव		
DIPR/C/18217/2025		

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन स.अभि. विभाग, जिला ग्रामीण खण्ड द्वितीय, बीकानेर		दिनांक-03.12.2025
पी.एच.ई.डी. कैम्पस इण्डस्ट्रियल एरिया के.जी. कॉम्प्लेक्स के पास, रानीबाजार, बीकानेर (334001) क्रमांक-7070-7089		
Notice Inviting Bid- 126to130/2025-26		
Bid for various works are invited to registered interested bidder upto 17.12.2025 at 18.00 hours. Other particulars of bid may be visited on the procurement portal www.sppp.raajasthan.nic.in & "http://eproc.raajasthan.gov.in" of the State. The approximate value of the procurement of Rs. 224.96 Lacs.		
NIT NO. 126	127	128
UBN NO. PHE2526 WSOB09326	PHE2526 WSOB09328	PHE2526 WSOB09329
	PHE2526 WSOB09330	PHE2526 WSOB09331
(नरेश कुमार रंगर) अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जिला ग्रामीण खण्ड-1, बीकानेर		
DIPR/C/18043/2025		

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड राजगढ़ (चूरु)		दिनांक-01.12.2025
क्रमांक- 1903-12		
ई-निविदा सूचना संख्या 12/2025-26		
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से तहसील राजगढ़ जिला चूरु में निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त श्रेणी के सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संबद्धों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संचालकों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/इका एवं दूर संचार विभाग/रेलवे इत्यादि में पंजीकृत संबद्धों, जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संबद्धों के समक्ष हों, से निर्धारित प्रश्न में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। आर.पी.डब्ल्यू.ए. 100 की शर्त लागू होगी। निविदा से संबंधित विवरण वेबसाइट http://dipr.raajasthan.gov.in/tenders.asp एवं विभागों की वेबसाइट http://eproc.raajasthan.gov.in व http://www.pwd.raajasthan.gov.in तथा http://sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है।		
NIB NO. PWD2526A4578, UBN NO. 1. PWD2526WSOB18153, 2. PWD2526WSOB18154		
अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड राजगढ़ (चूरु)		
DIPR/C/17969/2025		

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वेबसाइट : www.energy.raajasthan.gov.in/jvnl	
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वेबसाइट : www.energy.raajasthan.gov.in/avnl	
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वेबसाइट : www.energy.raajasthan.gov.in/jdvnl	
विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 64(2) के अंतर्गत सार्वजनिक सूचना	
सर्व संधारणा को सूचित किया जाता है कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर (सभी तीनों राजस्थान डिस्कॉम की ओर से) ने राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष याचिका संख्या 2365 / 2025 दायर की है। यह याचिका विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 तथा धारा 64 के अंतर्गत, तथा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग(रा.वि.आ.) द्वारा जारी रा.वि.आ. (टैरिफ विनियामक हेतु निबन्धन व शर्त) विनियम, 2025 के संदर्भ में, दोहरी-स्रोत आपूर्ति (Dual-Source Supply) से संबंधित प्रस्तावित टैरिफ संशोधनों की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई है।	
याचिका की प्रतियाँ निरीक्षण /अवलोकन हेतु तथा 100 रु के भुगतान पर विक्रय के लिए अयोग्य कार्यालय में तथा निम्न स्थानों पर उपलब्ध हैं:-	
1. जयपुर डिस्कॉम का मुख्य कार्यालय- विद्युत भवन, जेन एच, ज्योति नगर, जयपुर।	
2. अजमेर डिस्कॉम का मुख्य कार्यालय- अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, पंचशील नगर, माकवाली रोड, अजमेर।	
3. जोधपुर डिस्कॉम का मुख्य कार्यालय- जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, न्यू पावर हाउस, बसनी, जोधपुर।	
याचिका निगमों की वेबसाइट www.energy.raajasthan.gov.in/jvnl , www.energy.raajasthan.gov.in/avnl पर तथा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की वेबसाइट www.rerc.raajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।	
जो व्यक्ति टिप्पणियों / सुझाव प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे सहस्रक विवरणों सहित तथा रा.वि.आ. (कार्य का समायोजन) विनियम, 2021 के फार्म-3 में सार्थक पत्र के साथ, छह प्रतियों में, प्राप्ति अधिकारी, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, विनियामक भवन, सहकार मार्ग, जयपुर-302001 के कार्यालय में जमा कर सकते हैं, ताकि वे प्राप्ति अधिकारी को 24 / 12 / 2025 तक प्राप्त हो जाएं।	
टैरिफ में प्रस्तावित संशोधन	
1. टैरिफ में नई परिभाषा जोड़ना	
निम्नलिखित परिभाषा जोड़ी जाएगी:-	
"दोहरी-स्रोत आपूर्ति" ऐसी विद्युत आपूर्ति जो दो स्रोतों से प्रदान की जाती है, जिसमें दोनों स्रोतों से विद्युत का एक साथ या स्टैंडबाय उपयोग किया जा सके।"	
2. HT/EHT टैरिफ अनुसूचियों में नोट जोड़ना	
टैरिफ की सभी HT और EHT टैरिफ अनुसूचियों में निम्नलिखित नोट जोड़ा जाएगा:-	
"नोट: जो उपभोक्ता दोहरी-स्रोत आपूर्ति का लाभ उठाता है, बाहे वह एकसाथ उपयोग करे या स्टैंडबाय उपयोग करे, उसे संबंधित टैरिफ श्रेणी के लागू स्थाई शुल्क का दोगुना शुल्क लिया जाएगा।"	
राज.सं.बाद.सी./25/15323 जोधपुर 3095 (2025) अधीक्षण अभियन्ता (रंगुलेश्वरन)	

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा-2025 की उत्तरतालिका बाबत

बोर्ड द्वारा दिनांक 16.11.2025 को आयोजित राज्य स्तरीय प्रथिमा खोज परीक्षा-2025 (कक्षा-10 व कक्षा-12) की उत्तराई उत्तरतालििका बोर्ड की वेबसाईट पर www.rajeducationboard.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध कराया है। यदि किसी परीक्षार्थी को इस उत्तरतालििका के किसी प्रश्न के उत्तर में आपत्ति है तो वे बोर्ड के ई-मेल आईडी bserobjectons@gmail.com पर पर मण्यण के दिनांक 15.12.2025 तक निर्यासित प्राकुरण में आपत्ति दर्श करायें। इसके उपरान्त प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। जांक द्वारा प्राप्त आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जायेगी।

सविषय

राजस्थान हाईकोर्ट परिसर को बम से उडाने की फिर मिली धमकी

इससे पूर्व गत 31 अक्टूबर को भी यहां बम ब्लास्ट की धमकी का ई-मेल मिल चुका है, हालांकि राहत की बात है कि तलाशी में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट परिसर को बम से उडाने को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन को एक बार फिर धमकी मिली है। बीते चार दिन में यह दूसरा मौका है, जब हाईकोर्ट में बम धमाका करने की धमकी दी गई है। इससे पूर्व गत 31 अक्टूबर को भी यहां बम ब्लास्ट की धमकी का मेल मिल चुका है, हालांकि राहत की बात है कि तलाशी में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को भेजे गए इस मेल में हाईकोर्ट परिसर को बम से उडाने की बात कही गई है। ई-मेल की जानकारी मिलने ही उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई और पूरे हाईकोर्ट परिसर को खाली करवाया गया। वहीं न्यायाधीशों ने भी प्रकरणों की सुनवाई बीच में बंद कर दी।

हाईकोर्ट चौकी प्रभारी सुमेर सिंह ने बताया कि बम की सूचना मिलते ही पुलिस के बम निरोधक दस्ते और डॉंग स्क्वाड की ओर से पूरे हाईकोर्ट परिसर के चप्पे-चप्पे की जांच की गई। वहीं हाईकोर्ट परिसर से न्यायिक कर्मचारियों, अधिकारताओं व पक्षकारों को बाहर निकाला गया। डीसीपी साठव राजर्षि राज ने बताया कि बदमाश



राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन में मुख्यमंत्री ने सुनीं लोगों की समस्याएं।

वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। वीपीएन के कई प्रकार होते हैं। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी और मैन पावर है। उसका इस्तेमाल करके आरोपियों को जल्दी ही ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है कि जल्दी ही कुछ कामयाबी मिलेगी।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने कहा है कि हाईकोर्ट परिसर

की सुरक्षा को लेकर मजाक की सी स्थिति बन गई है। बीते डेढ़ माह में हाईकोर्ट को तीन बार बम से उडाने के मेल मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जांच एजेंसियां अभी तक यह तक मालूम नहीं कर पाई हैं कि ई-मेल कहां से आया है। हर बार मेल मिलने के बाद मुकदमों की सुनवाई बीच में बंद कर दी जाती है और कोर्ट

■ बम की धमकी के बाद सोमवार को पूरे हाईकोर्ट परिसर को खाली करवाया गया, न्यायाधीशों ने भी प्रकरणों की सुनवाई बीच में बंद की, जो कि 2 बजे बाद पुनः शुरू हुई

परिसर खाली करा लिया जाता है। जिससे एक और भय का माहौल पैदा हो गया है, वहीं मुकदमों की सुनवाई भी प्रभावित होती है। हाईकोर्ट के अधिकारता रामप्रताप सैनी ने कहा कि डढ़ माह में ही तीसरी बार हाईकोर्ट परिसर को बम से उडाने की धमकी मिलना गंभीर है। ऐसे में हाईकोर्ट प्रशासन व पुलिस प्रशासन को इन दोनों ईमेल की जांच करवानी चाहिए कि ये कहां से आ रहे हैं।

पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों की ओर से कोर्ट परिसर की पूरी तलाशी लेने के बाद क्लीन चिट दी गई। इसके बाद हाईकोर्ट में दोपहर दो बजे बाद से केंसों की सुनवाई शुरू हुई। हालांकि सुबह बम की धमकी मिलने के चलते अदालतों में सुनवाई नहीं हुई और हजारों प्रकरण प्रभावित हुए।

‘नई श्रम संहिताएं श्रमिक कल्याण हितैषी’

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नई श्रम संहिताएं श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव हैं। इनके माध्यम से मजदूर और कारोबार के हितों की सुरक्षा होगी और देश-प्रदेश के अनुकूल औद्योगिक वातावरण में वृद्धि होगी। उन्होंने केन्द्र सरकार की मंशानुसार नई श्रम संहिताओं के प्रदेश में समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देशित किया। शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में नवीन श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई श्रम संहिताओं के अनुसार सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र जारी करने की अनिवार्यता की गई है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। अटल ज्ञान केंद्रों को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार का सहयोग प्राप्त हुआ है। पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत राजस्थान के लिए 1047 पंचायत लर्निंग सेंटर (पीएलसी) की स्वीकृति प्रदान की गई है। करीब 232 करोड़ रुपए से अधिक की यह सहायता केंद्रों के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना, डिजिटल सुविधाएं और प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाएगी। इस सहायता से केंद्रों में उन्नत कंप्यूटर लैब, ई-लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में अटल ज्ञान केन्द्र खोलेगी भजनलाल सरकार

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना करेगी, ताकि ग्रामीण युवाओं को डिजिटल शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और कर्रियर परामर्श जैसी सुविधाएं मिल सकें। यह पहल राज्य सरकार के पिछले 2 वर्षों के समर्पित प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें विकास, शिक्षा और युवा सशक्तीकरण पर विशेष जोर दिया गया है।

■ प्रथम चरण में 3000 से अधिक आबादी वाली 1274 पंचायतें चिन्हित

■ इन जगहों पर ई-लाइब्रेरी, कंप्यूटर और इंटरनेट, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, कर्रियर परामर्श और क्षमता निर्माण कार्यक्रम को सुविधा होगी।

पहले चरण में 3000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत मुख्यालयों को प्राथमिकता दी गई है। अब तक 1274 केंद्रों को चिन्हित कर इनके लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। इस चरण के बाद प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा।

पिछले दो वर्षों में भजनलाल सरकार

ने युवा प्रोत्साहन, ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं। अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना इसी दिशा में एक और मील का पत्थर है, जो ग्रामीण युवाओं को शहरों के समकक्ष अवसर प्रदान करेगा। इन केंद्रों से न केवल शिक्षा का प्रसार होगा, बल्कि

जयपुर (कासं)। "राईजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट-2024" के उपरांत विभिन्न उद्यमियों और औद्योगिक ग्रुप्स ने एनसीआर क्षेत्र में अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की मंशा जाहिर थी। उनकी इस मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने अविलंब भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके उपरांत बीडा द्वारा लगभग 209 हैक्टेयर भूमि रीको को उपलब्ध कराई जायेगी। इस भूमि आवंटन से एक ओर औद्योगिक प्रतिष्ठानों को शीघ्रता से भूमि उपलब्ध करायी जा सकेगी, दूसरी ओर बीडा को लगभग 110 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति भी होगी, जिसका उपयोग बीडा द्वारा क्षेत्र के विकास एवं आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में किया जा सकेगा। राज्य सरकार के इस कदम से राज्य में औद्योगिक माहौल विकसित करने

■ रीको द्वारा जयपुर के जगतपुरा स्थित अपैरल पार्क में भी किया जाएगा औद्योगिक विकास

और 350 करोड़ बिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होगी। औद्योगिक विकास को गति देने और निवेशकों को राजस्थान में आकर्षित करने के उद्देश्य से रीको और जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपैरल पार्क, जगतपुरा से संबंधित लंबे समय से चल रही भूमि समस्या का सफलतापूर्वक समाधान कर लिया है। रीको द्वारा मुख्य महल रोड पर अपैरल पार्क की स्थापना वर्ष 2014 में लगभग 122 एकड़ पर की गई थी, जिसमें

टैक्सटाइल एवं अपैरल उत्पादों के लिये ही औद्योगिक भूमि का आवंटन किया गया था। खानेदारों द्वारा लंबे समय से उन्हें 25 प्रतिशत विकसित भूमि दिए जाने की मांग की जा रही थी। जेडीए के पास खानेदारों की मांग अनुसार विकसित भूमि दिए जाने हेतु पर्याप्त भूमि की अनुपलब्धता देखते हुए रीको से अतिरिक्त भूमि की मांग की गई थी।

रीको ने एक एमओयू जेडीए के साथ निष्पादित कर मुख्य 160 फीट रोड पर 4.57 हैक्टेयर भूमि खानेदारों से विवाद का समाधान करने के उद्देश्य से जेडीए को हस्तांतरित करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया है। जेडीए इस भूमि का उपयोग खानेदारों को दी जाने वाली विकसित वाणिज्यिक भूमि के रूप में कर सकेगा, जिसके लिये जेडीए ने आवश्यक कार्यवाही भी प्रारंभ

कर दी है। इस कदम से ना सिर्फ विभिन्न गतिविधियों के लिये भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी बल्कि जयपुर के प्रमुख महल रोड पर अन्य आर्थिक गतिविधियों जैसे सेवा क्षेत्र इत्यादि के लिये भी भूमि उपलब्ध हो सकेगी। गारमेंट एवं अपैरल सेक्टर में मुख्य नियोजन महिलाओं का होता है, इसलिए यहां महिलाओं के लिये भी रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकेंगे और ग्लोबल कैपेबिलिटी क्षेत्र, को-वर्किंग सेंटर, वाणिज्यिक परिसर, होटल आदि के निर्माण से पछे लिखे युवाओं को भी आने वाले समय में उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार के नए अवसर विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त हो सकेंगे। इस कदम से उन कारखानों ने भी राहत की सांस ली है जो लंबे समय से अपनी भूमि के एवज में विकसित भूमि की मांग कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने सुनीं राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन में लोगों की समस्याएं

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमावर को सचिवालय में दौरा करते हुए अचानक राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन सेंटर 181 पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने दो कॉलर्स नवलगढ़ (द्युन्धुर्न) के सुधीर और

■ 181 पर आ रही समस्याओं की बढ़ाई जाए मॉनिटरिंग : भजनलाल शर्मा



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन 181 का औचक निरीक्षण किया और परिवारियों की समस्याएं सुनीं।

शिकायतकर्ता नेमीचंद निवासी गोकलपुर गांव, वार्ड नंबर 29 (कोटपूतली-बहरोड़) ने मुख्यमंत्री को फोन पर बताया कि गोकलपुर गांव में वार्ड नंबर 29 में नाले की सफाई नहीं होने के कारण गंदा पानी निकलकर सड़क पर भरा हुआ है। जिससे आवागमन में लोगों को समस्या आ रही है तथा बीमारी का खतरा भी बना हुआ है। उन्होंने इस नाले की जल्द से जल्द सफाई कराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री के आदेश पर संबंधित कलक्टर ने नाले की तुरंत सफाई

करवाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 181 हैल्पलाइन दर्ज करवाकर उसका शीघ्र समाधान प्राप्त कर रहे हैं। संपर्क पोर्टल पर आ रही समस्याओं की अधिक से अधिक मॉनिटरिंग हो जिससे परिव्रादी की समस्या का समयबद्ध निस्तारण हो सके तथा उसे राहत मिले। मुख्यमंत्री ने पूरे प्रणाली को समझने एवं उसे और बेहतर बनाने के लिए स्वयं ही शिकायतकर्ताओं का कॉल अटेंड किया तथा उनकी समस्याओं का समाधान किया।

आधुनिक और भारतीय शिक्षा के समन्वय का मार्ग प्रशस्त करेगा शिक्षा बोर्ड : डॉ. एन.पी. सिंह



भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त आईएएस डॉ. एन. पी. सिंह ने प्रयागराज में संगोष्ठी को संबोधित किया।

में भारत के लगभग 120 महान नायकों की जीवनगाथाओं को भी शामिल किया है। यह शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को केवल नौकरी योग्य नहीं बल्कि रोजगार सृजन में सक्षम बनाएगी। बोर्ड का पाठ्यक्रम यूपीएससी, नेट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप की विकसित किया गया है। यह बोर्ड के समकक्ष है, यह कक्षा 9 से 12 तक की स्कूलों को मान्यता देती है। कक्षा 1 से 8

तक के मान्यता प्राप्त विद्यालय भारतीय शिक्षा बोर्ड से मान्यता ले सकते हैं। विशिष्ट अतिथियों में संयुक्त शिक्षा निदेशक राम नारायण विश्वकर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक पी. एन. सिंह, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संयुक्त कुल सचिव मेजर डॉ. हर्ष कुमार उपस्थित रहे। भारत स्वाभिमान के राज्य प्रभारी भगवान सिंह भी कार्यक्रम में सहभागी रहे। कार्यक्रम का संचालन वृज मोहन ने किया।

शिक्षण संस्थानों के आसपास नशा तस्करों के 35 ठिकानों पर दबिश

जयपुर । एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एनटीएफ) और आतंकवाद निरोधक दस्ता राजस्थान जयपुर (एटीएस) टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए शिक्षण संस्थानों (कॉचिंग-कॉलेज) के पास स्टूडेंट्स को नशे की लत में धकेलने वालों के पैतृस से अधिक ठिकानों पर दबिश देकर बाईस मामले दर्ज कर बाईस आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही पुलिस टीम ने आरोपियों के पास से 1 लाख 93 हजार 610 रुपए भी बरामद

किए हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन ने बताया कि काफी समय से जयपुर शहर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के आसपास मादक पदार्थों का अवैध व्यापार की शिकायतें मिल रही थी, जिससे विद्यार्थी नशे की गिरफ्त में आकर अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। इस सूचना पर महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार के निर्देशन में एटीएस-एएनटीएफ की पैतृस टीमें गठित कर जानकारी जुटाना शुरू किया। पुलिस

महानिरीक्षक एटीएस-एएनटीएफ विकास कुमार ने बताया कि मादक पदार्थ तस्कर शिक्षण संस्थानों के पास विद्यार्थियों को मादक पदार्थ देकर नशे की आदत डाल रहे थे। यह एक गंभीर और अनैतिक कार्य है। जो विद्यार्थियों के भविष्य को प्रभावित कर रहा है। इसकी रोकथाम के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की गई। जहां गठित टीम के पुलिसकर्मियों को संबंधित शिक्षण संस्थानों की वीदी पहना कर भेजा गया।

लेपर्ड के मूवमेंट के कारण एजी कॉलोनी में दिनभर रही दहशत

वन विभाग की टीम ने बजाज नगर क्षेत्र में सोमवार को सर्च ऑपरेशन चलाया, परंतु लेपर्ड हाथ नहीं लगा

जयपुर । राजधानी जयपुर के बजाज नगर स्थित एजी कॉलोनी में रविवार की देर शाम को लेपर्ड का मूवमेंट होता देख स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। इसके बाद लोगों ने वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सोमवार को सर्च ऑपरेशन चलाया, परंतु टीम



जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि यह एक वर्ष से भी कम उम्र का शावक है और अब मॉनिटरिंग टीमें लगातार निगरानी कर रही है। आशंका है कि शावक स्टेशन के पास नाले से होते हुए वापस जंगल की ओर चला गया। उसके जेएलएन रोड पार कर शिक्षा संकुल की ओर से आने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि लंबे समय से एमएनआईटी में भी लेपर्ड की मूवमेंट है।

अनिता कॉलोनी निवासी अरुण कुलश्रेष्ठ ने बताया कि सुबह करीब 5 बजे बजाज नगर एक्लेव कॉलोनी में मॉनिंग वॉक कर रही एक महिला को लेपर्ड का एक शावक दिखा। उसे देखते ही महिला ने शोर मचाया। जिस पर शावक वहां से भाग गया। इसकी जानकारी आसपास की कॉलोनियों में तेजी से फैल गई। कुछ देर बाद यह शावक सरस्वती कॉलोनी से होता हुआ अनिता कॉलोनी पहुंचा। यहां दो घरों में घुसा, जिसका मूवमेंट सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। चीफ वाइल्डलाइफ

वार्डन केसी अरुण प्रसाद की ओर से गठित क्विक रिसॉन्स टीम और रेंजर जितेंद्र सिंह शेखावत की टीम मौके पर लगातार निगरानी कर रही है। टीम आधुनिक तकनीक, ट्रैक्स और स्थानीय इन्फुट की मदद से लेपर्ड के मूवमेंट को ट्रैक कर रही है। जानकारी के अनुसार यह पूरा जोन झालाना लेपर्ड सफारी की परिधि से जुड़ा हुआ है। जहां पर करीब 40 से अधिक लेपर्ड रहवासा करते हैं। जहां से भोजन और पानी की तलाश में लेपर्ड आवासीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में शहर के कई हिस्सों में लेपर्ड की मूवमेंट की घटनाएं बढ़ने से वन विभाग भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। गौरतलब है कि राजधानी जयपुर में पिछले एक महीने में शहर में कई बार लेपर्ड के रिहायशी इलाकों में आने की घटना हो रही है। इस दौरान लेपर्ड सिविल लाइंस, गुर्जर की घाटी, विद्याधर नगर, शास्त्री नगर, चांदपोल, मोती डूंगरी इलाकों में देखे गए हैं।



मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों का सोमवार को अवलोकन किया।

जयपुर । मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सोमवार को सांगानेर के टीकरिया स्थित राजीविका विकास क्लस्टर लेवल फेडरेशन पहुंचे। जहां उन्होंने ब्लू प्रिंटीर एवं बगर प्रिंट से जुड़ी लखपति दीदियों से संवाद कर उनकी आजीविका गतिविधियों के अनुभव जाने। मुख्य सचिव ने आवकस्त किया कि राजस्थान की स्वयं सहायता समूहों

की इन प्रेरणादायक कहानियों को प्रधानमंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्य सचिव ने महिलाओं द्वारा निर्मित विविध उत्पादों की विशेष प्रशंसा भी की। साथ ही सेनेटरी नेपकिन यूनिट का अवलोकन किया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा ने कहा कि ग्रामीण महिलाएँ

अपने कौशल एवं परिश्रम से पूर्णतः स्वतंत्र एवं आत्मविश्वासी बन रही हैं। राजीविका प्लेटफॉर्म ने महिलाओं में उद्यमिता को मजबूत आधार प्रदान किया है। राजीविका की महिलाएं अपने उत्पाद सीधे ही बड़ी कंपनियों को बेच सकेगी उन्होंने आश्वासन दिया 'बायर सेक्टर मीट' की ओर व्यापक स्तर पर बढ़ावा जाएगा ।

सांगानेर में पहला राजकीय विधि महाविद्यालय प्रारंभ

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार “आपणो अग्रणी राजस्थान” के संकल्प की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। विधि के क्षेत्र में भविष्य बनाने की चाहत रखने वाले युवाओं को राज्य सरकार ने एक नवीन सौगात दी है। सांगानेर क्षेत्र में जयपुर जिले का प्रथम राजकीय विधि महाविद्यालय प्रारंभ किया गया है।

इस महाविद्यालय में तीन वर्षीय एल.एल.बी. पाठ्यक्रम का संचालन किया जाएगा, जिसकी 120 सीटों पर प्रवेश के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमति प्राप्त हो चुकी है तथा प्रवेश प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। राज्य सरकार द्वारा विधि महाविद्यालय के भवन हेतु 4.50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है तथा शीघ्र ही भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण कार्य के लिए टेण्डर जारी कर दिये जाएंगे। स्थाई भवन निर्मित होने तक अस्थाई तौर पर महाविद्यालय का संचालन शहीद पुनीत नाथ दत्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में किया जा रहा है।

■ विधि महाविद्यालय के भवन के लिए 4.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए

विधि महाविद्यालय के लिए राज्य सरकार ने 19 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इनमें सहायक आचार्य के सात, कनिष्ठ सहायक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के दो-दो तथा प्राचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षक, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सूचना सहायक, वरिष्ठ सहायक एवं बुक लिफ्टर के एक-एक पद शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार और युवाओं को प्रतिस्पर्धी युग के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए स्थापित नवीन विधि महाविद्यालय युवाओं के लिए एक सशक्त मंच साबित होगा। इससे युवा कानूनी शिक्षा ग्रहण कर न्याय और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कलेखनीय योगदान दे सकेंगे।

यूआईटी सचिव ललित गोयल की कार के पहिए की हवा निकालने की कोशिश

भीलवाड़ा। मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर पटेल नगर के सेक्टर 11 की कॉलोनीवासियों ने यूआईटी परिसर में पहुंचकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। पहले उन्होंने घेराव किया फिर जब अधिकारियों ने नहीं सुनी तो

■ **मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर पटेल नगर भीलवाड़ा सेक्टर 11 के कॉलोनीवासियों ने यूआईटी परिसर में पहुंचकर जबरदस्त प्रदर्शन किया**



भीलवाड़ा में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर पटेल नगर के सेक्टर 11 की कॉलोनीवासियों ने यूआईटी परिसर में प्रदर्शन किया।

गए। कॉलोनीवासियों का कहना है कि वर्ष 2010 में भूखंड आवंटन हुआ था। इसके बाद से किसी तरह की सुविधा नहीं दी जा रही है। यहां की टूटी सड़कों पर खुद की जेब से सीमेंट

लागाया है। यहां लाइट की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में करें तो क्या करें। कई पत्र लिख दिए, जनसुनवाई में शिकायत की लेकिन अभी तक आधारभूत सुविधाओं का विकास नहीं

किया। अब हमारे धैर्य का बांध टूटने लगा है। इस कारण सोमवार को यूआईटी परिसर पहुंचकर घेराव किया और अपने हक की मांगों के लिए आवाज बुलंद की।

काफी बहस के बाद विक्रम भट्ट को पकड़ा

उदयपुर, 8दिसम्बर । बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी को 30 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में उदयपुर पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया। पुलिस दोनों को सड़क मार्ग से उदयपुर लेकर आएगी। मंगलवार को कोर्ट में पेशी होगी।

उदयपुर डीएसपी छगन राजपुरोहित के अनुसार विक्रम भट्ट की गिरफ्तारी के लिए उदयपुर पुलिस चार दिन से मुंबई में डेरा डाले हुए थी। पुलिस लगातार विक्रम के संपादितो ड़िक्तानों पर दबिश दे रही थी। वह कब घर से बाहर आ रहा है और अंदर का रहा है। हर गतिविधि पर सीक्रेट तरीके से नजर रखी जा रही थी।उन्होंने बताया कि जब विक्रम भट्ट के फ्लैट के बाहर पहुंचने तो उसके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (पीएसओ) ने रोकने की कोशिश की। इस दौरान पीएसओ और पुलिस में बहस हो गई। घर के अंदर बैठे विक्रम और उसकी पत्नी यह सब देख रहे थे। मौका मिलते ही फ्लैट से दोनों को गिरफ्तार

चम्बल नदी में मिला युवक का शव

कोटा।नयापुरा इलाके की चम्बल नदी की छोटी पुलिया पर चम्बल नदी मे एक युवक का शव मिला। चम्बल नदी में शव तेरने की सूचना मिलने पर नगर निगम की गौताखोर टीम व पुलिस मौके पर पहुंची। नगर निगम गौताखोर ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि चंबल की छोटी पुलिया के पास भीड़ एकत्रित है तथा नदी में कुछ संदिग्ध दिखाई दे रहा है।

सूचना प्राप्त होते ही नगर निगम गौताखोर रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम द्वारा मौके का निरीक्षण कर रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारम्भ किया गया। रेस्क्यू के दौरान चंबल नदी से एक अज्ञात पुरुष का शव बरामद किया गया। प्रारंभिक पहचान के अनुसार मृतक के पास से आधार कार्ड मिला, मृतक की शिनाख्त चन्द्रप्रकाश कोली के रूप में हुई। शव को बाहर निकालकर कार्यवाही हेतु थाना नयापुरा पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है।

भारत को विश्वगुरु बनाने की आधारशिला है नई शिक्षा नीति : देवनानी

उदयपुर, 8 दिसम्बर। नई शिक्षा नीति 2020 ऐसी जीवंत दृष्टि है जो राष्ट्र के विकास का प्राण है। यह सिर्फ काजगी दस्तावेज नहीं है बल्कि भारत को विश्व गुरु बनाने की आधारशिला है। इससे ऐसी नई पीढ़ी तैयार होगी जो राष्ट्र प्रथम की अवधारणा से ओतप्रोत होगी। विधासभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोमवार को मोहनलाल सुखाड़िया विवि शैक्षणैतर कर्मचारी संघ की ओकर से आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन एवं सेमिनार में नई शिक्षा नीति पर जन प्रतिनिधियों को बहभागिता स्वयं पर संगोष्ठी के उद्घाटन स्त्र में मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए यह विचार व्यक्त किए।

देवनानी ने कहा कि कस्तीरंगन के साथ मिलकर नई नीति को अंतिम रूप देने में उनका भी योगदान रहा है। उन्होंने इसे लागू करने में शिक्षक, शिक्षणैतर कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों के सम्वन्त प्रयास की आवश्यकता जताई। विशेषकर जनप्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में बोलते हुए देवनानी ने कहा कि जनप्रतिनिधि स्थानीय स्तर की आवश्यकता के अनुरूप सुझाव देते हैं जिससे नीति निर्धारण की प्रामाणिकता

■ भट्ट दम्पति सहित अब तक 4 हो चुके गिरफ्तार

कर लिया। डीएसपी ने बताया. हम 6 सदस्यों की टीम के साथ 3 दिसंबर को मुंबई पहुंचे थे। मुंबई पुलिस का मिनिमम सपोर्ट लिया गया ताकि मिशन सीक्रेट रहे। विक्रम भट्ट का पूरा नाम और पेशा बताने की बजाय पुलिस ने सिर्फ ये ही बताया कि विक्रम नाम का वॉटेड आरोपी है। उस पर 420 का मुकदमा है। उदयपुर पुलिस उसे पकड़ने के लिए यहां आई हुई है।ऐसे में मुंबई पुलिस के दो कॉन्स्टेबल हमारे साथ रहे। हमारी टीम विक्रम भट्ट के हर ड़िक्ताने पर नजर बनाए हुए थी। रविवार (7 दिसंबर) को विक्रम भट्ट और उसकी पत्नी के मुंबई में जुहु स्थित गंगाभवन कॉम्प्लेक्स में होने की जानकारी थी। इस कॉम्प्लेक्स में कई फ़िल्मी कलाकार रहते हैं।

डीएसपी ने बताया पुलिस टीम गंगाभवन कॉम्प्लेक्स पहुंची तो विक्रम

भट्ट के 3 से 4 पीएसओ ने बाहर ही रोकने की कोशिश की। पीएसओ ने पूछा. आप कौन और कहां से हो, तब उन्हें सिरफ़ इतना ही कहा कि वे डीएसपी हैं, कहां से हैं, ये नहीं बताया। उन्हें बताया कि विक्रम भट्ट से पूछताछ करनी है।पीएसओ ने मना करते हुए कहा कि साहब और उनकी पत्नी इस वक्त घर पर नहीं है। बाहर गए हैं।

काफी देर तक उनके निजी सुरक्षा गार्डों से बहस हुई। इसके बाद पुलिस को सख्ती से पेश आना पड़ा।पुलिस और उसके पीएसओ के बीच हो रही बहस का विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे में देख रहे थे। पुलिस टीम ने सभी पीएसओ की दूर किया। डुप्लेक्स फ्लैट के बाहर काफी जद्दोजहद की, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। पुलिस बार.बार दरवाजा पीटती रही। करीब आधे घंटे बाद पुलिस

सख्ती से पेश आई तो दरवाजा खोला। विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी ने गिरफ्तारी का विरोध किया। दोनों ने पुलिसकर्मियों से काफी बहस की। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। उस वक्त फ्लैट में उनके दोनों बच्चे नौकर और 4 से 5 पीएसओ थे।

डीएसपी छगन राजपुरोहित ने बताया कि विक्रम भट्ट,पत्नी श्वेतांबरी भट्ट समेत फरार 6 आरोपियों को उदयपुर पुलिस ने नोटिस भेजा था। विक्रम और श्वेतांबरी को रविवार को मुंबई से गिरफ्तार किया। डीएसपी ने बताया कि इस मामले में पुलिस तीसरी बार मुंबई गई थी। इससे पहले 18 नवंबर को विक्रम भट्ट के को.प्रोड्यूसर महबूब अंसारी और वेंडर संदीप विश्‍नश्वात्रिभुवन को भी मुंबई से ही गिरफ्तार कर लेकर आए थे। दोनों जेल में हैं। वहीं, एक बार मामले की जांच को लेकर मुंबई गए थे। विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी समेत मामले में कुल 4 गिरफ्तारी हो चुकी है।

ठगों ने प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना में भी सेंध लगाई

आवदेन के नाम पर ठगे 2.59 लाख रुपए

■ पीडित ने पुलिस में दी शिकायत

नवंबर को एक कॉलर ने खुद को इस योजना का अधिकारी बताते हुए संपर्क किया। कॉलर ने अपना नाम दीपक सिंह बताया और कहा कि उनका आवेदन स्वीकृत हो गया है, आगे की प्रक्रिया पूरी कर ली। पीडित ने बताया कि 1 दिसंबर को 5 हजार रुपए फॉर्म व रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर इंडियन ओवरसीज बैंक में जमा करवाए। इसी दिन पत्नी राखेश्वरी गुप्ता के नाम पर 44 हजार 950 रुपए का एग्रीमेंट चार्ज के जमा करवाया। इसके बाद 2 और 3 दिसंबर को दवा सप्लाई के नाम पर दो बार में 1

लाख 5 हजार रुपए दिल्ली की बंधन बैंक में निपटी के जरिए जमा करवाए। सभी ट्रांजेक्शन के दौरान आरोपी द्वारा सभी रसीदें और दस्तावेज की पीडीएफ भेजी ताकि भरोसा बना रहे। 4 दिसंबर को आरोपी ने फिर कॉल कर कहा कि योजना महिला के नाम पर स्वीकृत हुई है, इसलिए सरकार की ओर से 2 लाख 50 हजार रुपए की सफ़िडी मिलेगी, जिसके लिए 18 प्रतिशत जीएसटी 45 हजार रुपए देना होगा। इस पर पीडित को शक हुआ। इंटरनेट पर सत्यापन करने पर पता चला कि सफ़िडी पर जीएसटी नहीं लगता। पीडित ने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत कर क्रिश्चियनगंज थाने में लिखित शिकायत दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

हादसे में चालक की मौत

उदयपुर। हादसों के लिए कुख्यात गोगुंदा हाईवे पर एक बार फिर भीषण सड़क हादसा हो गया। सोमवार को गोगुंदापुंढिडवाड़ा हाईवे पर उखलियात सुरंग के समीप तेज रफ्तार मार्बल पत्थर से भरे कंटेनर का चलते समय टायर फट गया, जिससे अनियंत्रित कंटेनर चट्टान से टकरा गया।

हादसे में कंटेनर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पर पुलिसए हाईवे टीम के भगवत सिंह झाला तथा 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची। गंभीर रूप से घायल चालक को एंबुलेंस से गोगुंदा अस्पताल ले जाया गया,जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोगुंदा थाना पुलिस के अनुसार मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान दिनेश भाई पिता राजा भाई कंजारिया, निवासी जमादवाक,जिला जामनगर (गुजरात) के रूप में हुई। पुलिस ने बेकरिया थानाधिकारी उत्तम सिंह मेडतिया को सूचना देते हुए मृतक के परिजनों को भी हादसे की जानकारी दी ।

थानाधिकारी उत्तम सिंह मेडतिया ने बताया कि गुजरात नंबर का कंटेनर गोगुंदा की ओर से मार्बल पत्थर लेकर कांडला बंदरगाह जा रहा था। इसी दौरान आगे का टायर फट गया। कंटेनर के अनियंत्रित होने पर चालक ने बचने के लिए कूदने का प्रयास किया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

संडे बाजार के व्यापारियों का विरोध

भीलवाड़ा। इंड्रा मार्केट में संडे बाजार लगाने वाले लोगों के खिलाफ स्थाई व्यापारियों ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पहले बाजार को सुबह 10 से 12 बजे तक बंद कर राख विरोध जताया। फिर नगर निगम परिस्र में पहुंचकर संडे बाजार की वजह से हो रही अख्यवस्थाओं को लेकर नारेबाजी की। बाद में महापौर राकेश पाठक नहीं मिले तो उनके निवास स्थान पर जाकर ज्ञापन सौंपा और अख्यवस्था को सही कराने की मांग की। एसोसिएशन के अनुसार संडे को बाजार लगाने वालों के कारण जाम की स्थिति पैदा होती है। स्थाई दुकानदारों को दुकानों में जाने का रास्ता नहीं मिलता है। अगर इसके लिए तकाजा किया जाता है तो संडे बाजार वाले धमकी देते है। कई बार विवाद की स्थिति बन जाती है। यहां तक कि संडे बाजार वाले महिलाओं को आगे करके स्थाई दुकानदारों के लिए दुविधा खड़ी कर देते हैं।

चाकूबाजी में पिता-पुत्र और हमलावर कायल

भीलवाड़ा। शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र की नया बापू नगर कॉलोनी में अलाव तापने के दौरान हुए विवाद के बाद चाकूबाजी में पिता-पुत्र और हमलावर घायल हो गया।

प्रतापनगर थाना पुलिस के अनुसार नया बापूनगर इलाके में रविवार रात एक युवक के अलाव तापते समय गाली-गलौज करने पर विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि सौरभ झा बिना वजह गाली-गलौज कर रहा था। पड़ोसी महेशदास ने खिड़की से आवाज देकर उसे गली गलौज नहीं करने की बात कही तो झा और बिफर गया और गाली-गलौज करते हुए महेश दास को नीचे आने की धमकी दी, जब महेशदास नीचे आया तो दोनों के बीच बहस हो गई। सौरभ अपने घर से सब्जी काटने वाला चाकू लेकर आया और महेशदास के सीने, षट व हाथ पर हमला कर दिया। घायल महेशदास नीचे गिर गया।

देश में हुमायूँ की औलादें जिंदा नहीं : डॉ. तोगड़िया

■ **महाराणा प्रताप व छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज आज भी सक्रिय राजनीति में हैं**

कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता।”मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम पर अपनी राय रखते हुए, उन्होंने इसे देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया। तोगड़िया ने जोर दिया कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी बांग्लादेशी या अन्य विदेशी नागरिक भारतीय मतदाता सूची में शामिल न हो

काशी-मथुरा में मंदिर निर्माण का संकल्प : हिंदुओं की आस्था के प्रमुख केंद्रों पर बात करते हुए, तोगड़िया ने काशी विश्वनाथ मंदिर और श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का जिक्र किया। उन्होंने दोहराया कि परिषद का लक्ष्य है कि “सभी मंदिर बनेंगे।” उन्होंने हिंदू समुदाय को संगठित करने के लिए चलाए जा रहे

देशव्यापी अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से गांव-गांव और शहर-शहर में सामूहिक “हनुमान चालीसा” का पाठ आयोजित किया जा रहा है। हिंदू वेलनेस सेंटर और हेल्पलाइन : संगठन के सेवा कार्यों पर प्रकाश डालते हुए डॉ. तोगड़िया ने बताया कि परिषद की ओर से हिंदू वेलनेस सेंटर और एक हिंदू हेल्प लाइन शुरू की गई है, जिससे देश में किसी भी जरूरतमंद हिंदू को सहायता पहुंचाई जा सके। पत्रकार वार्ता के दौरान चंद्रसिंह जी और राजेंद्र गोखर सहित अन्य स्थानीय पदाधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले, राजेंद्र गोखर और प्रदीप सांखला ने डॉ. तोगड़िया का भीलवाड़ा पहुंचने पर स्वागत किया।

अजमेर में दो बसों की टक्कर में 15 से अधिक यात्री घायल

अजमेर । शास्त्री नगर चुंगी नाका के पास सोमवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे उस समय चीख-पुकार मच गई जब तेज रफ्तार आ रही प्राइवेट बस ने आगे चल रही दूसरी प्राइवेट बस को जोरदार टक्कर मारी। हादसा इतना भीषण था कि दोनों बसें क्षतिग्रस्त हो गईं, जिसके कुछ देर के लिए सड़क पर यातायात बंद हो गया। हादसे में करीब 15 से अधिक यात्री घायल हो गए, जिन्हें एंबुलेंस के माध्यम से स्थानीय लोगों और पुलिस द्वारा जेएलएन अस्पताल पहुंचाया, जहां प्रार्थमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने क्रेन की मदद से बसों को मार्ग से हटाकर यातायात खुलावाया।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नरवर से अजमेर आ रही एक निजी बस ने ओवरटेक करने के चक्कर में आगे चल रही दूसरी बस को पीछे से टक्कर मार दी। बस में महिलाएं, छोटे बच्चे सहित करीब 60 यात्री सवार थे। हादसे के बाद दोनों बसों में चीख-पुकार मच गई। सीट से उछलकर कई यात्री एक-दूसरे पर गिर गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 15 से 18 यात्री मामूली व मध्यम चोटों आई हैं। किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय

पैरोल का उद्देश्य अपराधी का पुनर्वास : हाईकोर्ट

■ बेटे की हत्या के दोषी पिता को मिली पैरोल

दिया था। यह अस्वीकृति मुख्य रूप से पुलिस उपायुक्त, (पंथिम) और परीवीश एवं कारागार कल्याण अधिकारी की रिपोर्ट पर आधारित थी, जिन्होंने परिवार और पड़ोसियों की आपत्तियों के आधार पर पैरोल की सिफारिश नहीं की थी। कोट में याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित एमीक ब्यूरी अंजलि कौशिक ने तर्क दिया कि पैरोल का उद्देश्य अपराधी का पुनर्वास और समाज में पुनर्समावेश है। चूंकि याचिकाकर्ता ने ओपन एयर कैप में रहते हुए जेल में अच्छा आचरण प्रदर्शित किया है, इसलिए पैरोल से इनकार करना गलत है। राजस्थान हाईकोर्ट ने पैरोल प्रणाली

पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्तमान पैरोल व्यवस्था में ऐसे कैदियों के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो बेकर हैं, जिनका कोई अभिभावक नहीं है या परिवार का समर्थन नहीं है। कोर्ट ने कनाडा जैसे विकसित देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां कान्युनिटी करेशन सेंटर और रेजिडेंशियल फैसिलिटीज हैं, जो बिना घर और परिवार वाले पैरोलियों को आवास और भोजन उपलब्ध कराती हैं। कोर्ट ने कहा कि यह समय है कि सरकार अपनी पैरोल नीति पर पुनर्विचार करें, ताकि ऐसे कैदियों की स्थितियों का ध्यान रखा जा सके जिनके पास रहने के लिए जगह या देखभाल करने वाला कोई नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने कहा कि पैरोल का उद्देश्य कैदी के अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करना है, और यह पुनर्वास और समाज में पुनसमावेश का एक अवसर है।

मामा की हत्या

रामगंजमंडी, (निसं)। स्थानीय पुलिस की सूझबूझ व सजगता से शुक्रवार को सगे भाणेज द्वारा दोस्तों के साथ मिलकर मामा की हत्या करने तथा हत्या के बाद अंतिम संस्कार की भी तैयारी करने का चौकाने वाला खुलासा हुआ है।

पुलिस ने सोमवार को हत्या का खुलासा करने के साथ मृतक नवनीत सोनी की हत्या के मामले में फरार सगे भाणेज गौरव सोनी व उसके तीन दोस्तों को गिरफ्तार करने में भी सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण अवनीश शर्मा ने बताया कि 5 दिसम्बर को पुलिस थाना रामगंजमंडी पर दर्ज हत्या के प्रकरण में वॉिश्र अभियुक्तगण मृतक नवनीत सोनी के सगे भाणेज गौरव सोनी व उसके दोस्त प्रदीप सिंह, विक्रम सिंह उर्फ विक्की व रक्षित अग्रवाल उर्फ गोटेया को गिरफ्तार कर हत्या की वारदात का पर्दाफाश करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रामगंजमंडी में सगे भाणेज गौरव सोनी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने मामा नवनीत सोनी की हत्या करके मृतक नवनीत सोनी की लाश का अंतिम संस्कार कर सबूत मिटाने की फिफाक में है। सूचना पर थानाधिकारी मनोज सिकरवार ने मौके पर पहुंचकर रेखा तो मृतक नवनीत सोनी की लाश का अंतिम संस्कार करने हेतु मोक्ष धाम में लेकर जाने की तैयार चल रही थी।

गहराई से जुड़ा हुआ है। यह अध्ययन किशोर मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में नीति-निर्माण और स्कूलों के पाठ्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

गीतांजली हॉस्पिटल के डीन डॉ

अब तक 8738 प्रवासी राजस्थानियों ने राजस्थानी दिवस आयोजन में पंजीकरण कराया

राजस्थानियों ने आयोजन में शांतिपूर्ण ढंग से भाग लेने के लिए अपना पूंजीकरण कर दिया है। विज्ञान, कला, व्यापार, शिल्प, स्वास्थ्य, उद्योग, खेल, साहित्य आदि के माध्यम से सामाजिक सेवा सहित, विभिन्न श्रेणियों के लोगों को प्रभावी रूप से राजस्थानियों के उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए आयोजन प्रभावी राजस्थानी सम्मान अवार्डों के माध्यम से समारोह का आयोजन किया जाएगा।

प्रियंका ने आगे बताया कि 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्यसमिति ने एक प्रस्ताव पारित करके वंदे मातरम् को राष्ट्रीय गीत घोषित किया था।

आप भारत वास्तव में इंडिया जैसे
घटनाओं को दोबारा होने से रोकना
चाहता है, तो सुधार केवल किसी एक
एम्पलाइन को दंडित करने तक सीमित
नहीं रहने चाहिए। सुधार पूरे सिस्टम को
मजबूत करने वाले हों, जैसे ए.टी.एफ.
टैक्स को तर्कसंगत बनाना, नियामक
क्षमता को मजबूत करना, प्रशिक्षण दाने
को विस्तार देना, हवाईअंशुओं
आधुनिकीकरण करना और एयरलाइंस
को तैयारी के उच्च बुनियादी मानकों को
मल्टी कराना देश की विमानन
लागतों/क्षारों का प्रयोग नींव पर नहीं
टिक सकती। इंडिया की यह घटना एक
चेतनावनी का तरह है: भारत को केवल
क्षमता नहीं, बल्कि मजबूती भी
बनानी होगी।

केशवन ने अपनी पोस्ट में लिखा,

कमेटी ने सुनील शर्मा के नाम की सिफारिश राज्यपाल से की। इसके बाद राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए।

बजे 6ई 1073 फ्लाइट लेकर फुकेट(थाईलैंड) निकल गए थे। गोवा पुलिस ने रेस्टोरेंट बार मालिक गौरव और सौरभ लुधिया के दिल्ली के घर टीमा घुसने लेकिन वो घर पर नहीं मिले। इनके घर पर गोवा पुलिस ने नोटिस चप्पा किया है, गोवा पुलिस को रिक्वेस्ट 7 दिसंबर को दोनों के खिलाफ एलओसी जारी कराई थी, जिससे दोनों शरा छोड़कर न भाग सकें लेकिन दोनों पहले ही फरार हो चुके हैं। गोवा पुलिस ने सीबीआई को मदद से इंटरपोल के जरिए इनकी लोकेशन करने के लिए कोषाश शुरू कर दी है।

परीक्षा पेपर लोक मामले का खुलासा होने के बाद से फरार चल रहा था। वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2020 के पेपर लोक का मामला सामने आने के बाद बांसावाड़ा जिले के राजतलाब थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। राजस्थान एसओजी इसकी बालोतारा जिले के कालावा गांव का निवासी है और वह बाड़मेर जिले के रामजी का गोल गांव के सरकारी स्कूल में अध्यापक पद पर तैनात है। उसकी गिरफ्तारी एसओजी ने 50 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की थी।

आइए मिलकर जश्न मनाएं खास ऑफ़र्स के साथ!



**Offers Valid Till
Stocks Last**



SCAN TO
CONNECT
TO SHOWROOM
NEAR YOU



E-BOOK
TODAY AT
WWW.MARUTISUZUKI.COM

**Contact us at
1800-102-1800**

Terms and conditions apply. Please contact your nearest dealership for details. Features, accessories, and specifications may vary by variant and are subject to change without prior notice. Images are for illustration purposes only. Offers and prices may differ by variant, model, location, and city, and are subject to change or withdrawal without notice. Offer values represent the maximum applicable benefits and include consumer, exchange, and institutional/fleet offers (where applicable) on select models. The effective price for Alto K10 of ₹3.17 Lakh has been calculated after deducting the applicable consumer offer of ₹25 000, scrappage bonus of ₹25 000, and rural/ISL offer of ₹2 500 from the ex-showroom price of ₹3.69 Lakh. The effective price for S-presso of ₹2.97 Lakh has been calculated after deducting the applicable consumer offer of ₹25 000, scrappage bonus of ₹25 000, and rural/ISL offer of ₹2 500 from the ex-showroom price of ₹3.49 Lakh. The effective price for WagonR of ₹4.40 Lakh has been calculated after deducting the applicable consumer offer of ₹30 000, scrappage bonus of ₹25 000, and rural/ISL offer of ₹3 100 from the ex-showroom price of ₹4.98 Lakh. The effective price for Celerio of ₹4.17 Lakh has been calculated after deducting the applicable consumer offer of ₹25 000, scrappage bonus of ₹25 000, and rural/ISL offer of ₹2 500 from the ex-showroom price of ₹4.69 Lakh. 3 Crore sales is for entire Maruti Suzuki portfolio.



अष्टवतु हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्यॉइन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एम.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स: 0141-2373513 कोटा कार्यालय: बलायथा हाउस प्रिंटर/प्रिण्टिंग शिवाजी भवन, कोटा। फोन: 2386021, 2386032, फैक्स: 0744-2386033 बीकानेर कार्यालय: इ.कुमारा नाथ, हुमान हत्या, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रतु चवत, नूरी चाना के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स: 0145-2624665 जालौर कार्यालय: - जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया प्रथम, जालौर। फोन: 2266222, 2264223, फैक्स: 02973-226424 हिजोनीसिटी कार्यालय: - जी 1-1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिजोनीसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 भुवना कार्यालय: एम-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, ब्रुक, फोन: 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908

